भारत सरकार

भारतीय अर्थव्यवस्था
पर
श्वेत पत्र

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली
फरवरी, 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था
पर
श्वेत पत्र

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली
फरवरी, 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र

एक सिंहावलोकन

वर्ष 2014 में जब हमने सरकार बनाई, अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी; लोक वित्त बुरी अवस्था में थी; अत्यधिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता व्याप्त थी, और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अत्यधिक संकटमय स्थिति थी। अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से सुधारने और शासन व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी विशाल थी। उस समय हमारी सरकार दयनीय अवस्था के संबंध में श्वेत पत्र लाने से बचती रही। उससे एक नकारात्मक धारणा बनती और निवेशकों सहित सभी का विश्वास डगमगा गया होता। उस समय की मांग लोगों को आशान्वित करना, घरेलू और वैश्विक, दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करना, अत्यधिक आवश्यक सुधारों के लिए सहायता प्रदान करना था। सरकार 'राष्ट्र-प्रथम' और न कि राजनैतिक छवि को चमकाने में विश्वास करती थी। अब जबकि हमने अर्थव्यवस्था को स्थिर कर लिया है और इसे सुधार और विकास की स्थिति में ला दिया है, यह आवश्यक हो गया है कि हम यूपीए सरकार द्वारा विरासत के रूप में छोड़ी गई प्रतीयमानतः अलंघ्य चुनौतियों का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसार करें। "वर्ष 2014 से पूर्व की अवधि की प्रत्येक चुनौती पर हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन द्वारा जीत हासिल की गई। इससे देश सतत उच्च विकास के अटल मार्ग पर आ गया है। यह हमारी सही नीतियों, यथार्थपूर्ण मंशाओं और उपयुक्त नीतियों के जरिए संभव हुआ है।"[1]

"श्वेत पत्र" के उद्देश्य:

- प्रथम, इसमें संसद के माननीय सदस्यों और भारत की जनता को इस सरकार के वर्ष 2014 में सत्ता में आने पर विरासत में प्राप्त प्रशासन की प्रकृति और सीमा, आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराने का प्रयास किया गया है।
- द्वितीय, यह संसद के माननीय सदस्यों और जनता को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, इसे वर्तमान में और अमृत काल में लोगों की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने में सशक्त और सक्षम बनाने की उन नीतियों और उपायों के बारे में अवगत कराता है जो हमारी सरकार ने अपनाए हैं।

[1] बजट भाषण, वित्त वर्ष 2025

- तृतीय, ऐसा करने में, यह राजनीतिक लाभ के बजाय शासन के मामलों में राष्ट्रीय हित और राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोच्चता पर एक व्यापक, अधिक सूचित बहस उत्पन्न करने की उम्मीद करता है।
- चतुर्थ, "नई प्रेरणाओं, नई चेतना, नए संकल्पों के साथ खुद को राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध करना, क्योंकि देश अपार संभावनाओं और अवसरों को उपलब्ध कराता है।"[2]

श्वेत पत्र में वर्ष 2004 में चुनी गई डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए वैकल्पिक रूप से "यूपीए सरकार" शब्द का उपयोग किया गया है, और वर्ष 2014 में चुनी गई श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए "हमारी सरकार" का उपयोग किया गया।

भाग 1 में, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की वृहद आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई है, जहां दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति, उछाल के दौर के दौरान लापरवाही के साथ अत्यधिक ऋण देने के बाद रूग्ण बैंकिंग क्षेत्र, और उच्च नीतिगत अनिश्चितता ने भारत के कारोबारी वातावरण को प्रभावित किया और अपनी छवि और अपने भविष्य के बारे में लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाई जबकि वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2004 में उच्च विकास क्षमता के साथ एक स्वस्थ और समुत्थानशील अर्थव्यवस्था सौंपी गई थी। इस भाग में वित्त वर्ष 2004-2014[3] के दौरान लोक वित्त के कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता पर भी चर्चा की गई है। दौरान कई घोटालों हुए जिन्से राजकोष के लिए भारी राजस्व नुकसान हुआ और राजकोषीय और राजस्व घाटे नियंत्रण से बाहर हो गए। वर्ष 2014 में हमारी सरकार को एक बहुत ही जीर्णक्षीर्ण अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसकी नींव को आत्मनिर्भर दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए पुनर्निमाण करना पड़ा।

भाग 2 यूपीए सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचारी घोटालों का उल्लेख करता है।

भाग 3 में यह दर्शाया गया है कि कैसे हमने अर्थव्यवस्था को बदल दिया, देश की छवि का पुनर्निर्माण किया और बेहतर भविष्य के लिए हमारे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को फिर से जागृत किया। अब राष्ट अपने खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

---

[2] प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण, 15 अगस्त, 2023

[3] वित्त वर्ष का अर्थ है अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष।

भाग 1: 2014 की अर्थव्यवस्था - नुकसान की विरासत

वर्ष 2004 में एक दुरूस्त अर्थव्यवस्था से वर्ष 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक

1. **यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जो अधिक सुधारों के लिए तैयार थी लेकिन इसने इसे अपने दस वर्षों में गैर-निष्पादित बना दिया।** वर्ष 2004 में, जब यूपीए सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया, सौम्य विश्व आर्थिक वातावरण के बीच अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत (उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक और वित्त वर्ष 2004 में 9 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर के साथ) की दर से बढ़ रही थी। वर्ष 2003-04 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि

   > *"अर्थव्यवस्था विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन के संदर्भ में लचीले मोड में प्रतीत होती है, एक ऐसा संयोजन जो निरंतर व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ विकास गति के समेकन के लिए बड़ी गुंजाइश प्रदान करता है।"*[4]

2. **विडंबना यह है कि यूपीए नेतृत्व जो 1991 के सुधारों का श्रेय लेने में शायद ही कभी विफल रहता है, उसने 2004 में सत्ता में आने के बाद उसे छोड़ दिया।** एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के शिखर पर खड़े होने के बावजूद यूपीए सरकार ने पिछली एनडीए सरकार द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण करने के लिए शायद ही कुछ किया था। 2004 और 2008 के बीच के वर्षों में, एनडीए सरकार के सुधारों के प्रभावों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। यूपीए सरकार ने उच्च विकास दर का श्रेय लिया लेकिन इसे मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार की बजट स्थिति को मजबूत करने और भविष्य की विकास संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए उच्च विकास के वर्षों का लाभ उठाने में विफलता उजागर हुई। जैसा कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने उपयुक्त रूप से कहा,

   > *"पहले पांच वर्षों की उच्च वृद्धि और कम मुद्रास्फीति मुख्य रूप से वर्ष 2002-07 के वैश्विक आर्थिक उछाल और वर्ष 2004 से पहले किए गए व्यापक, उत्पादकता बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों के कारण थी। यूपीए*

[4]आर्थिक सर्वेक्षण 2003-04, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

सरकार की आर्थिक नीतियां शुरू में औसत दर्जे की थीं और जैसे-जैसे दशक बीतता गया, उनकी स्थिति और खराब होती गई।"[5]

3. **इससे भी बुरी बात यह है कि यूपीए सरकार ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद किसी भी तरह से उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने की अपनी खोज में, व्यापक आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।** आर्थिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, अर्थव्यवस्था गहरे कुप्रबंधन और उदासीनता के तहत जूझ रही थी।

"मूल रूप से, यूपीए सरकार का दशक उच्च विकास और निवेश के वर्षों के सुनहरे अवसरों के बावजूद, भारत की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार करने में विफल रहा"।[6]

4. **ऐसा ही एक नींव जिसे यूपीए सरकार ने बुरी तरह कमजोर किया था, वह मूल्य स्थिरता थी।** वर्ष 2009 और 2014 के बीच मुद्रास्फीति बढ़ गई और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2014 के बीच छह वर्षों के लिए उच्च राजकोषीय घाटे ने आम और गरीब परिवारों पर संकट का ढेर लगा दिया। वित्त वर्ष 2010 से वित्त वर्ष 2014 तक की पांच साल की अवधि में, औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर दोहरे अंकों में थी। वित्त वर्ष 2004 और वित्त वर्ष 2014 के बीच, अर्थव्यवस्था में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2 प्रतिशत थी **(चार्ट 1)**।

[5] शंकर आचार्य: "यूपीए की आर्थिक विरासत - अच्छी, बुरी या बदसूरत?", बिजनेस स्टैंडर्ड, 25 फरवरी 2014(https://www.business-standard.com/article/opinion/shankar-acharya-upa-s-economic-legacy-good-bad-or-ugly-114022501240_1.html)

[6] बिजनेस स्टैंडर्ड में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ शंकर आचार्य का लेख, 25 फरवरी 2014 https://www.business-standard.com/article/opinion/shankar-acharya-upa-s-economic-legacy-good-bad-or-ugly-114022501240_1.html

चार्ट 1 : यूपीए के वर्षों में मुद्रास्फिति के रूझान

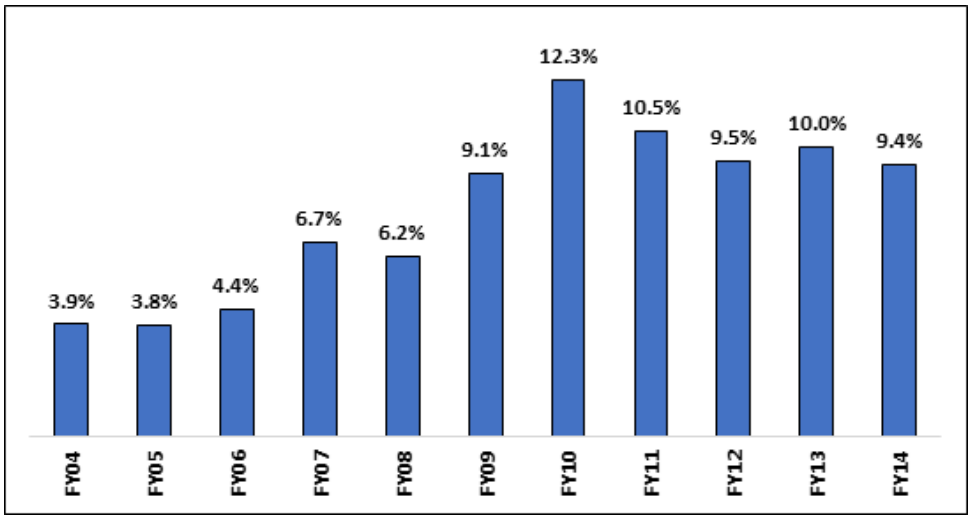

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋण

5. **यूपीए सरकार की सबसे बड़ी और अपयश विरासत बैंकिंग संकट थी।** जब वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात 16.0 प्रतिशत था और जब उन्होंने पद छोड़ा था, यह 7.8 प्रतिशत था। सितंबर 2013 में, पुनःसंरचित ऋणों सहित यह अनुपात बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वाणिज्यिक ऋण निर्णयों में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3 प्रतिशत तक चढ़ गया था **(चार्ट 2)**। इससे भी बदतर बात यह थी, अशोध्य ऋणों की उच्च प्रतिशतता का कम आंकलन किया गया था।

चार्ट 2: यूपीए के कार्यकाल के दौरान गैर-निष्पादित आस्तियों में वृद्धि

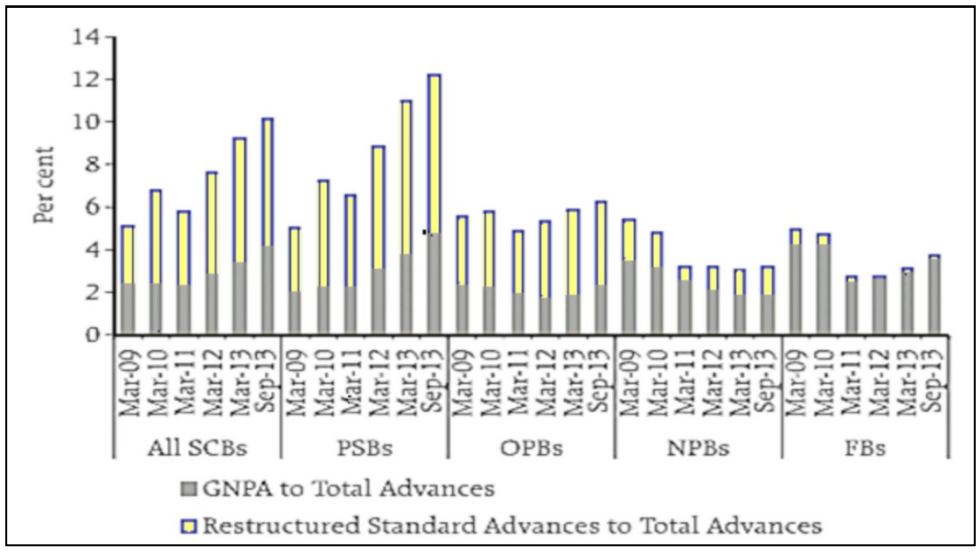

स्रोत: चार्ट 2.13, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंक संख्या 8, दिसंबर 2013

6. **वर्ष 2014 में बैंकिंग संकट विशाल था और दांव पर लगी पूर्ण राशि बहुत बड़ी थी।** मार्च 2004 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 2012 में यह 39.0 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा, सभी समस्या वाले ऋणों (प्रॉब्लम लोन) को मान्यता नहीं दी गई थी। बहुत कुछ सामने आना बाकी था। मार्च 2014 में प्रकाशित क्रेडिट सुइस रिपोर्ट के मुताबिक, एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली शीर्ष 200 कंपनियों पर बैंकों का लगभग 8.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है। उन ऋणों में से लगभग 44 प्रतिशत (3.8" लाख करोड़ रुपये) को अभी तक समस्या आस्तियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इससे ही जीएनपीए अनुपात में 67 प्रतिशत की और वृद्धि होती। 2018 में, एक संसदीय पैनल को लिखित जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा

"वर्ष 2006-2008 की अवधि में बड़ी संख्या में अशोध्य ऋण उत्पन्न हुए थे।"[7]

अत्यधिक बाह्य अरक्षितता

7. **एक ऐसे युग में जब पूंजी प्रवाह का बोलबाला है, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत की बाह्य रक्षितता बढ़ गई है।** यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, ईसीबी 21.1 प्रतिशत (वित्त वर्ष 04 से वित्त वर्ष 14) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 तक नौ वर्षों में, यह 4.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 2013 में जब अमेरिकी डॉलर तेजी से बढ़ा तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। यूपीए सरकार ने बाह्य और वृहद आर्थिक स्थिरता से समझौता किया था और मुद्रा 2013 में गिर गई थी। 2011 और 2013 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने उच्च से निचले स्तर तक भारतीय रुपया 36 प्रतिशत तक गिर गया **(चार्ट 3)।**

[7] यह नोट प्रोफेसर रघुराम जी राजन द्वारा 6 सितंबर, 2018 को संसद प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, डॉ मुरली मनोहर जोशी, सांसद के अनुरोध पर तैयार किया गया था

चार्ट 3: 2011 और 2013 के बीच भारतीय रुपये की लगातार गिरावट

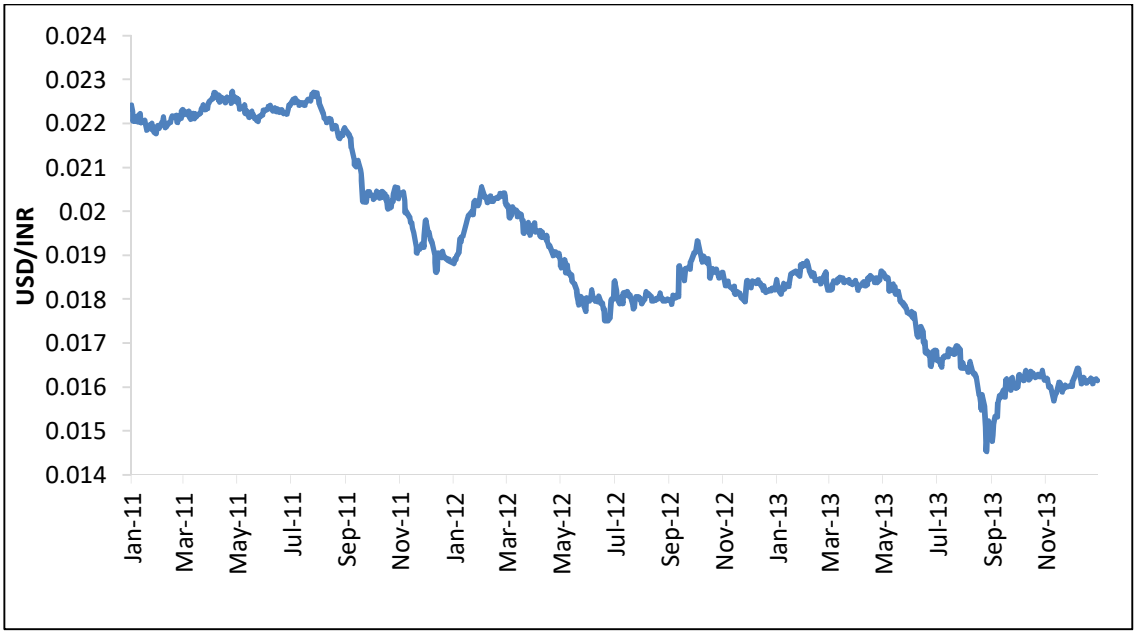

टिप्पणी: चार्ट प्रति अमरीकी डालर भारतीय रूपये को दर्शाता है। स्रोतः एफआरईडी

विदेशी मुद्रा संकट और एफसीएनआर (बी) विंडो

8. **अनिवासी भारतीयों के लिए प्रसिद्ध विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर (बी) डिपॉसिट विंडो वास्तव में मदद के लिए एक कॉल थी जब विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी कमी थी।** यूपीए सरकार के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2011 के 294 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में करीब 256 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया था। सितंबर 2013 के अंत तक, विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने के आयात के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त था, जो मार्च 2004 के अंत में 17 महीनों से नीचे आ गया था। विदेशी ऋण के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात वित्त वर्ष 2011 के 95.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2014 में 68.8 प्रतिशत रह गया। लगातार बिगड़ती स्थिति से उबारने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को अगस्त-सितंबर 2013 में उच्च प्रीमियम पर अमरीकी डालर जमा राशियों आकर्षित करने के लिए एफसीएनआर (बी) के लिए एक विशेष विंडो खोली।

9. **स्व-निर्मित उपरोक्त दुर्दशा का महंगा समाधान 1991 के पुनः चलने की पुनरावृत्ति के रूप में सामने आया जब भारत को भुगतान संतुलन संकट के दौरान सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करना पड़ा था।** हालांकि, 1991 से एक संदिग्ध अंतर यह है कि एफसीएनआर (बी) (26.6 बिलियन अमरीकी डालर) के माध्यम से एनआरआई से जुटाई गई राशि 1991 के आईएमएफ बेलआउट (2.2 बिलियन

अमरीकी डालर) से 12 गुना अधिक थी! इस उच्च लागत वाले डॉलर के ऋण का मोचन वित्त वर्ष 2016 में निर्वहन के लिए पीछे छोड़ दिया गया था, एक देयता जिसका अब हमारी सरकार द्वारा बिना किसी व्यवधान के भुगतान किया गया है।

लोक वित्त का घोर कुप्रबंधन

10. **वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट - स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज - के प्रति यूपीए सरकार की प्रतिक्रिया उस समस्या से कहीं अधिक खराब थी जिसे उसने संबोधित करने की मांग की थी।** यह वित्त पोषण और उसे बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की क्षमता से परे था। दिलचस्प बात यह है कि प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं था जो इसे प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। जीएफसी के दौरान, भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2009 में धीमी होकर 3.1 प्रतिशत रह गई, लेकिन वित्त वर्ष 2010 में तेजी से 7.9 प्रतिशत तक सुधर गई (तालिका 1)। जीएफसी के दौरान और बाद में वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर आईएमएफ डेटा का उपयोग करते हुए एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अन्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित था। विभ्रांत प्रोत्साहन को एक वर्ष से आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

तालिका 1: भारत जीएफसी वर्ष 2008 द्वारा बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था

	जीएफसी-प्रभावित वर्ष	
उभरती अर्थव्यवस्था	**2008**	**2009**
ब्राजील	5.1	-0.1
चीन	9.6	9.4
भारत	**3.9**	**8.5**
इंडोनेशिया	7.4	4.7
कोरिया	3.0	0.8
मेक्सिको	0.9	-6.3
रूस	5.2	-7.8

	जीएफसी-प्रभावित वर्ष	
विकसित अर्थव्यवस्था	**2008**	**2009**
कनाडा	1.0	-2.9
फ्रांस	0.1	-2.8
जर्मनी	1.0	-5.7
इटली	-1.0	-5.3
जापान	-1.2	-5.7
यूनाइटेड किंगडम	-0.2	-4.5
यूनाइटेड स्टेट्स	0.1	-2.6

स्रोतः आईएमएफ और एमओएसपीआई

यूपीए सरकार के वित्त मंत्री ने वर्ष 2011 में अपने एक भाषण में इस बात को स्वीकार किया था:

भारत, अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, विकसित दुनिया में 2008 की वित्तीय उथल-पुथल से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ था....[8]

11. **यूपीए सरकार के तहत, सार्वजनिक वित्त को एक खतरनाक स्थिति में लाया गया था।** वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2014 के बीच लगातार छह वर्षों के लिए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए भारत के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का अनुपात कम से कम 4.5 प्रतिशत था। यह छह वर्षों में से तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच था, एक में 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के बीच और दो वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक था। राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.07 प्रतिशत से चार गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2009 में 4.6 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2010 में यह बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गई, वित्त वर्ष 2011 में थोड़ी गिरावट के साथ 3.3 फीसदी और वित्त वर्ष 2012 में फिर बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई।

12. **बेलगाम राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर ढकेल दिया।** यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यूपीए सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन[9] के लिए गठित केलकर समिति ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय स्थिति का उपयुक्त वर्णन किया। प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित हैः

"भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में राजकोषीय संकट के कगार पर है, यदि इस स्थिति से उत्पन्न गंभीर प्रतिकूल परिणामों को कुशल और समयबद्ध तरीके से टालना है तो राजकोषीय समेकन में तेजी लाने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों को एक अनिवार्य आवश्यकता बना दिया जाना है। चालू वर्ष, 2012-13 की प्रवृत्तियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि यदि तत्काल मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो राजकोषीय घाटा लगभग 61 प्रतिशत हो सकता है जो सकल घरेलू उत्पाद के 51 प्रतिशत के बजट अनुमान से कहीं अधिक है। बेलगाम राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक ऋण के असंपोषणीय स्तरों की ओर ले जाता है, व्यापक आर्थिक असंतुलन के विभिन्न रूपों का कारण बन सकता है जिनके माध्यम से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है।"

[8] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=77144
[9] https://dea.gov.in/sites/default/files/Kelkar_Committee_Report.pdf

13. **यदि हम जो देखते थे, वह अधिक चिंतादायी था, जो हम नहीं देख सके, वह अधिक समस्याकारी था।** केलकर समिति का यह संकेत देना सही था कि अंतर्निहित घाटा बजटीय घाटे से अधिक है। वित्त वर्ष 2013 से पहले भी ऐसा ही था। यूपीए सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी नकद सब्सिडी के बदले में वित्तीय वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 तक पांच वर्षों में कुल 1.9 लाख करोड़ से अधिक की विशेष प्रतिभूतियां दी गईं। प्रत्येक वर्ष के लिए सब्सिडी बिल में उनके समावेश ने राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को बढ़ा दिया होगा जैसा कि **चार्ट 4** में दिखाया गया है।

चार्ट 4: राजकोषीय और राजस्व घाटे: देखा और अनदेखा

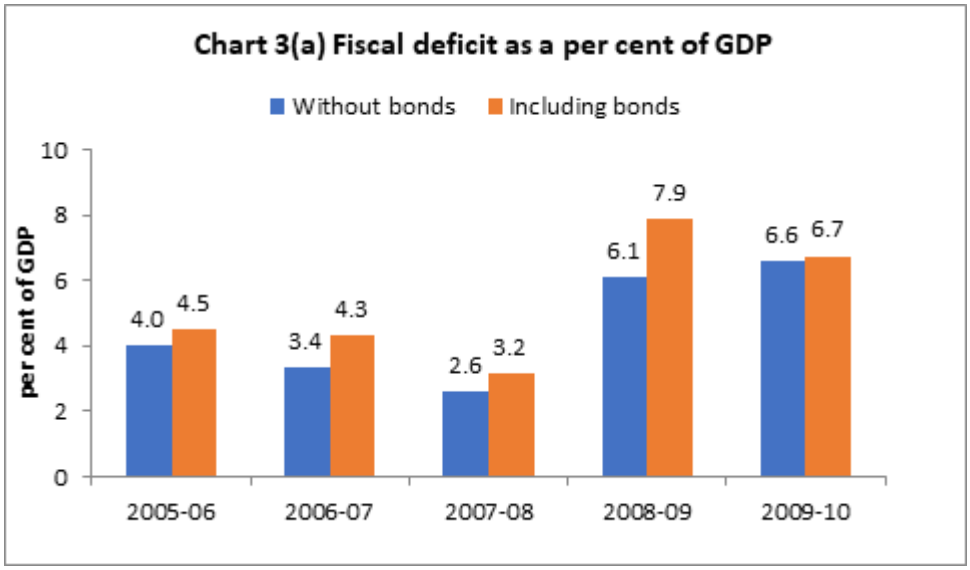

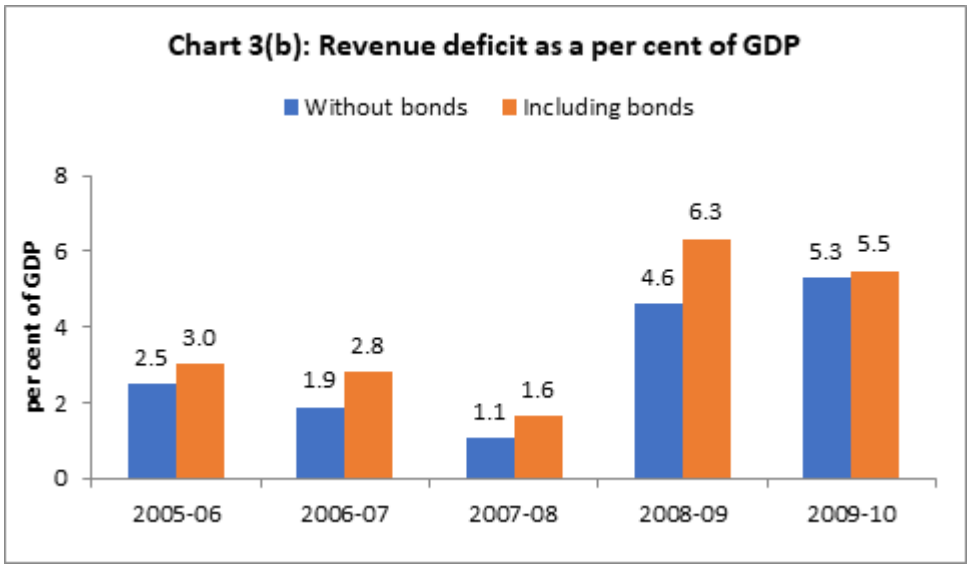

स्रोत: विभिन्न बजट दस्तावेज़, एमओएसपीआई (2011-12 की कीमतों पर बैक सीरीज)

14. **अपने राजकोषीय कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप, यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा अंत में अपेक्षा से कहीं अधिक हो गया, और बाद में यह 2011-12 में अपने बजट की तुलना में बाजार से 27 प्रतिशत अधिक उधार लेने लगी (चार्ट 5)।** यह वैश्विक वित्तीय संकट के तीन साल बाद हुआ जब सरकार को बजटीय अनुमान से अधिक खर्च करने के बजाय राजकोषीय रूप से समेकित होना चाहिए था।

चार्ट 5: 2011-12 के राजकोषीय आंकड़ों में भारी वृद्धि

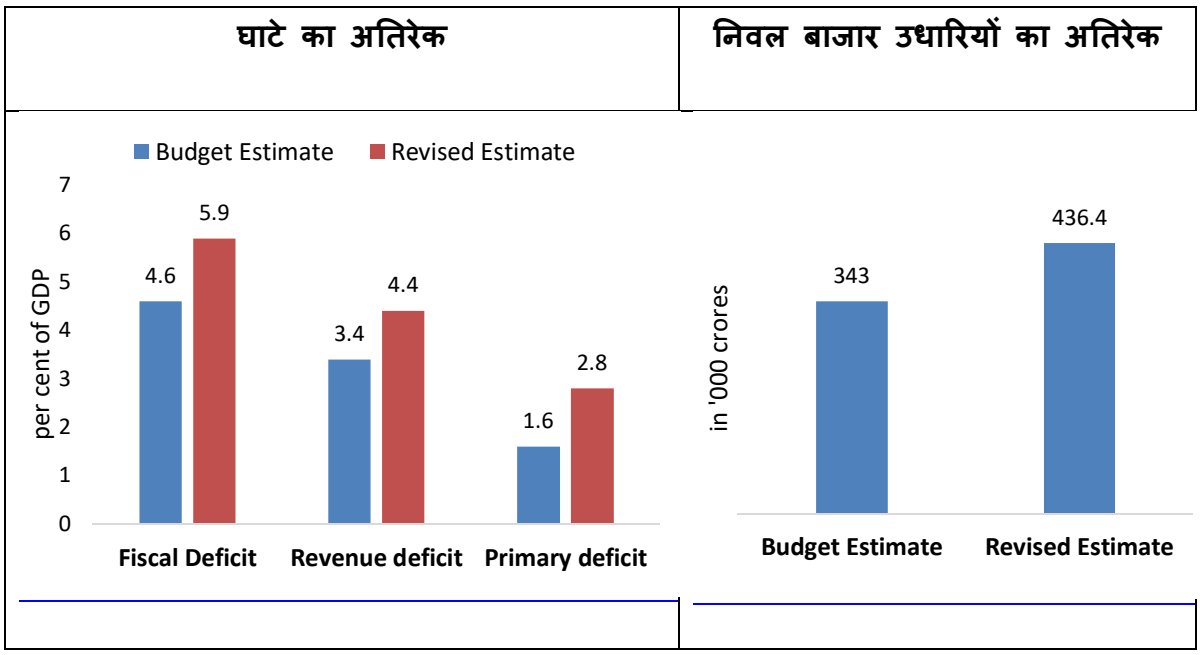

स्रोत: वित्त वर्ष 2013 के लिए केंद्रीय बजट

15. **राजकोषीय घाटे का बोझ अर्थव्यवस्था के लिए सहन करने हेतु विशाल हो गया।** इसलिए, वित्तीय वर्ष 2005 से 2014 में नीतिगत विफलताओं के परिणामस्वरूप अत्यधिक अनुत्पादक सरकारी उधार, अप्रभावी व्यय रणनीतियों और राजकोष को होने वाले राजस्व घाटे को समझने के लिए गहराई में जाना महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार की बाजार उधारियों में भारी वृद्धि

16. **वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया देने के बहाने (साथ ही यह तर्क देते हुए कि भारत संकट से प्रभावित नहीं था), यूपीए सरकार ने अपने उधार का विस्तार किया और बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगाया।** आरबीआई के अनुसार, "सरकार के शुद्ध बाजार उधार कार्यक्रम (दिनांकित प्रतिभूतियों) का आकार आठ वर्षों में लगभग 9.7 गुना बढ़कर 2012-13 में 4.9 ट्रिलियन हो गया। **इसके अलावा, सरकार ने 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों के माध्यम से 1.16 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण का सहारा लिया)"** [10]

[10] स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 4 मार्च, 2013 को जारी मुद्रा और वित्त पर आरबीआई रिपोर्ट, 2009-12 (पृष्ठ 47) का अध्याय 3 ('भारत में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय: एक आकलन')।

दोषपूर्ण प्राथमिकताएं और अवसंरचना एवं आस्ति सृजन की स्पष्ट उपेक्षा

17. यूपीए सरकार ने न केवल बाजार से अत्यधिक उधार लिया, बल्कि उसने जुटाई गई धनराशी का उपयोग अनुत्पादक रूप से किया। जब हम 2004-2014 के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय की मात्रा, गुणवत्ता और समय का मूल्यांकन करते हैं तो यह पहलू स्पष्ट हो जाता है। पूंजीगत व्यय, जो अवसंरना में सार्वजनिक निवेश को वित्तपोषित करता है, को उन 10 वर्षों में प्राथमिकता से हटा दिया गया था, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक बाधाएं पैदा हुईं और इसकी विकास क्षमता से समझौता हुआ। जैसा कि **चार्ट 6** में दर्शाया गया है, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय (ब्याज भुगतान को छोड़कर) वित्त वर्ष 2004 में 31 प्रतिशत से घटकर जो वित्त वर्ष 2014 में 16 प्रतिशत हो गया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की आपूर्ति बाधित रही। अत्यधिक घाटे से कुल मांग को लगातार बढ़ावा देने के साथ, इसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति, उच्च चालू खाता घाटा और एक ओवरवैल्यूड मुद्रा हुई जो सभी 2013 में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए जब भारतीय रुपया ऐसी अविवेकपूर्ण नीतियों के बोझ के नीचे दब गया। सरकारी व्यय को अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों की दिशा में तैयार किया गया था।

चार्ट 6: ए कैपिटल इन्डिफरेंस

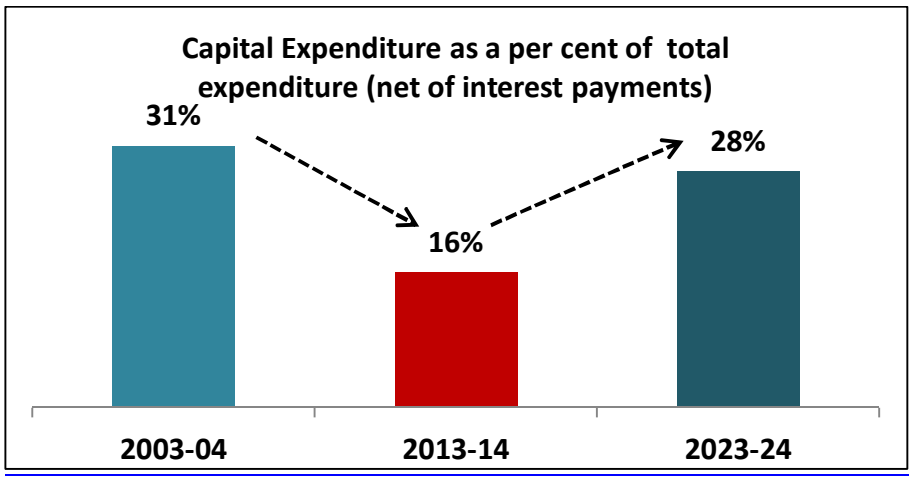

स्रोत: बजट दस्तावेज

18. **अवसंरचना के सृजन की स्पष्ट उपेक्षा और संभारतंत्रीय बाधाओं की चुनौतियों से औद्योगिक और आर्थिक विकास लड़खड़ाया।** यूपीए सरकार ने भविष्य के लिए अवसंरचना निर्माण के लिए अपनी असफलता को स्वीकारा। एक जनहित याचिका के उत्तर में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए एक शपथ-पत्र में यूपीए सरकार ने

कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 40000 किलोमीटर में से 24000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को एनडीए शासन के दौरान 1997 से 2002 तक जोड़ा गया था। उसके बाद, यूपीए के पिछले दस वर्षों में केवल लगभग 16,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विस्तार किया गया है।[11]

19. **रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने भी यूपीए सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व व्यय को इंगित किया है।** आरबीआई द्वारा 2009 में प्रकाशित वृहत आर्थिक और मौद्रिक विकास रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 'वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में तेजी से वृद्धि हुई जो छठे वेतन आयोग के भुगतान, कृषि ऋण माफी पर व्यय, तेल और उर्वरक सब्सिडी और प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों[12] को परिलक्षित करता है'। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान बढ़े हुए राजस्व व्यय विस्तार का एक बड़ा भाग (जीएफसी) से पहले घोषित किया गया था। जीएफसी ने संप्रग सरकार को राजनीतिक लाभ के लिए किए गए अपने अत्यधिक राजस्व व्यय को समाज के लिए कोई आर्थिक लाभ दिए बिना छिपाने का मौका दे दिया।

20. **खराब नीति नियोजन और निष्पादन के परिणामस्वरूप यूपीए के वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया गया**, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की योजनाओं की प्रभावशीलता अपंग हो गई। 14 प्रमुख सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालयों[13] में, यूपीए सरकार (2004-14) की अवधि के दौरान बजटीय व्यय का कुल 94,060 करोड़ रुपये खर्च नहीं किया गया था, जो उस अवधि के दौरान संचयी बजट अनुमान का 6.4 प्रतिशत था **(चार्ट 7)**। इसके विपरीत, एनडीए सरकार (2014-2024) के दौरान, बजटीय व्यय का 37,064 करोड़ रुपये, जो संचयी बजट अनुमान का 1 प्रतिशत से भी कम है, को खर्च नहीं किया गया था।

---

[11] https://sansad.in/getFile/debatestextmk/16/II/2307(f).pdf?source=loksabhadocs

[12] https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=11345#ANN1

[13] 14 सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालयों में कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शामिल हैं।

चार्ट 7: 14 प्रमुख सामाजिक और ग्रामीण मंत्रालयों में अल्प व्यय (बजटीय व्यय-वास्तविक व्यय)

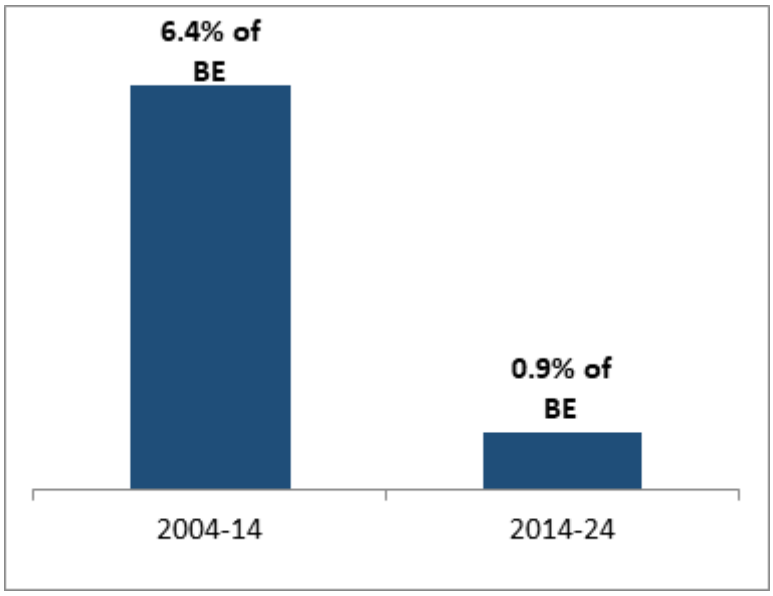

टिप्पणी: अल्प व्यय बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के अंतर को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 के लिए, यह व्यय के संशोधित अनुमान और बजट अनुमान के बीच का अंतर है; ब.अ. बजट अनुमानों को दर्शाता है।
स्रोत: बजट दस्तावेज

21. **यूपीए सरकार के दौरान भारतीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य व्यय भी चिंता का विषय था।** तथ्य यह है कि वित्त वर्ष 2014 में भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) का 64.2 प्रतिशत था (वित्त वर्ष 2005 में टीएचई के प्रतिशत के रूप में 69.4 प्रतिशत ओओपीई से थोड़ा सुधार के साथ) का अर्थ था कि स्वास्थ्य व्यय गरीब परिवारों के लिए गरीबी का मार्ग होने के अलावा, भारतीय नागरिकों की जेब को खाली करता रहा।
22. **अनुत्पादनकारी खर्च की सरकार की प्राथमिकता का मतलब था कि उत्पादक निवेश के बजाय उपभोग के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया गया था।** उदाहरण के लिए, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों, जिन्हें जीएफसी से पहले लागू किया गया था, ने 18,060 करोड़ रुपये[14] के अतिरिक्त बकाया भुगतान के साथ वित्त वर्ष 2009 के लिए 7,975 करोड़ रुपये का निवल वित्तीय निहितार्थ इंगित किया। वर्ष 2008 की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडी) की राजकोषीय लागत 52,000 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत)[15] थी। विश्व बैंक नीति शोध वर्किंग

[14] https://doe.gov.in/sites/default/files/6cpchighlights%281%29%281%29.pdf
[15] https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=17091

पेपर द्वारा ऋण माफी पहल के प्रभाव का आकलन किया गया। अपेक्षाओं के विपरीत, पेपर को योजना के परिणामस्वरूप बेहतर निवेश, खपत या बढ़ी हुई मजदूरी का कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बजाय, अध्ययन से पता चलता है कि कार्यक्रम के तहत बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की पूरी राशि के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने के बाद, बैंकों ने उच्च डिफ़ॉल्ट जिलों से कम डिफ़ॉल्ट दरों वाले जिलों को ऋण का पुन: आवंटन किया। इसके अलावा, उच्च-डिफ़ॉल्ट वाले जिलों (यहां तक कि क्रेडिट योग्य लोगों) में उधारकर्ताओं ने राहत कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, जो भविष्य[16] में अधिक उदार क्रेडिट प्रवर्तन या इसी तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित क्रेडिट बाजार हस्तक्षेपों की प्रत्याशा में कार्यनीतिक डिफ़ॉल्ट का संकेत देता है।

एक अर्थशास्त्री ने कहा,

"सरकार आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए डरपोक रवैया अपना रही है। इसका ध्यान भविष्य के बारे में सोचने और विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के बजाय वोट जीतने के लिए लोकलुभावन नीतियों पर अधिक रहा है, "वोट के बदले सब्सिडी देने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था।"[17]

23. **दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास हेतु प्रयोजन की ऐसी कमी थी कि रक्षा तैयारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी नीतिगत पक्षाघात से बाधित किया गया था।** कमजोर नेतृत्व तथा इरादे और कार्य की लगातार कमी के परिणामस्वरूप रक्षा संबंधी तैयारी कम हो गई। वर्ष 2012 तक, युद्ध के लिए तैयार उपस्कर और गोला-बारूद की कमी हमारी सेनाओं के समक्ष एक पुरानी समस्या थी। हम लड़ाकू विमानों की खरीद की लंबी प्रक्रिया को भी याद कर सकते हैं जो कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। यहां तक कि भारतीय सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन गॉगल्स देने का फैसला भी वर्षों[18] तक लटका रहा।

24. **तटीय जिलों में औद्योगिक विकास पर प्रतिबंध।** समुद्र, महासागर और तटीय क्षेत्र अपनी जैव विविधता और अपनी आर्थिक क्षमता के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपीए

---

[16] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2524163 (विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सं, 7109)

[17] अशोक देसाई, अर्थशास्त्री https://www.indiatoday.in/india/north/story/india-manmohan-singh-upa-scams-policy-paralysis-gdp-growth-rate-economy-178631-2014-01-27

[18] अप्रेल 2018 में महाबलीपुरम में डिफेन्स एक्सपो में प्रधानमंत्री का भाषण https://pib.gov.in/ViewVideo.aspx?V_ID=51670&MinID=1325&VPRID=44195&Day=&Month=4&Year=2018

सरकार ने विनियमों को घुमा-फिरा दिया जिससे 83 तटीय जिलों की आर्थिक वृद्धि और विकास को अधिकांशत प्रतिबंधात्मक प्रकृति को रोक दिया। इससे तटीय क्षेत्रों में समुदायों और जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लाभों को प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया। इस अधिसूचना ने इन जिलों में पर्यटन क्षेत्रों को भी कमजोर बना दिया। इसके अलावा, यूपीए सरकार द्वारा सीआरजेड मानदंडों की शुरूआत ने तटीय जिलों में विकास परियोजनाओं पर उनके नियंत्रण को भी कठोर कर दिया, इस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके उपलब्ध विकल्पों को रोक दिया। हमारी सरकार ने पर्यावरणीय और विकासात्मक प्राथमिकताओं का संतुलित विचार प्रस्तुत किया है।

सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ने अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल दिया

25. यूपीए सरकार के शासन का दशक (या इसका अभाव) नीतिगत खामियों और घोटालों जैसे कि सार्वजनिक संसाधनों (कोयला और दूरसंचार स्पेक्ट्रम) की अपारदर्शी नीलामी, पूर्वव्यापी कराधान की आशंका, अस्थिर मांग प्रोत्साहन और गैर-लक्षित सब्सिडी और पक्षपात के उपक्रम के साथ बैंकिंग क्षेत्र द्वारा लापरवाह ऋण, आदि देना शामिल था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुमानों के अनुसार, 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़े 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने सरकारी खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये की कटौती की थी, सरकारी खजाने में 1.86 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि ने राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया और निवेश केन्द्र के रूप में भारत की छवि को खराब तरीके से प्रतिबिंबित किया।[19]

26. **कोयला घोटाले ने 2014 में देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था।** 2014 से पहले, कोयला ब्लॉकों का आवंटन ब्लॉकों के आवंटन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था। कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से बाहर रखा गया था और इस क्षेत्र में निवेश और क्षमता का अभाव था। इन कार्रवाइयों की जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई और 2014 में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों/ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया।

[19] इसके बारे में अधिक जानकारी भाग 2 में प्रस्तुत है।

27. **यूपीए सरकार को जुलाई 2012 में हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बिजली कटौती के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें 62 करोड़ लोग अंधकार में चले गए और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई।** देश में अंधेरा छा गया था, जबकि कोयला और गैस जैसे ईंधन की कमी के कारण 24,000 मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी थी। पूरा क्षेत्र निष्क्रियता और नीतिगत पक्षाघात के दुष्चक्र में पहुंच गया, जिसमें एक छोर पर अधिशेष उत्पादन क्षमता और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त निवेश थे, जबकि दूसरे छोर पर उपभोक्ता के लिए बड़ी बिजली कटौती हुई थी। जब हमारी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के दो-तिहाई (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ट्रैक किए गए 100 कोयला संयंत्रों में से 66) के पास कोयले का अत्यल्प भंडार था, जिसका मतलब है कि सात दिनों से भी कम का कोयला भंडार था। यह अनिश्चितता समग्र बिजली की कमी को बढ़ा रही थी। गांवों में प्रति दिन करीब 12 घंटे बिजली मिलती थी। किसानों को बहुत कम अवधि के लिए मिलती थी, जिससे वे अपनी फसलों की सिंचाई करने में सक्षम नहीं होते थे। अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लाइनें भी अत्यधिक अपर्याप्त थीं।

28. यूपीए सरकार के अंतर्गत बिजली की कमी को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भी बार-बार इंगित किया गया था। अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2008 में, बैंक ने नोट किया "भारत की 55-60 प्रतिशत सिंचित भूमि भूजल द्वारा आपूर्ति की जाती है ट्यूबवेल पंपों के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण इनपुट है.... अनियमित और सीमित आपूर्ति और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण सेवा की गुणवत्ता खराब है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वगामी सिंचाई और क्षतिग्रस्त पंपिंग उपकरण से फसल का नुकसान हो सकता है।" विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, जून, 2012 में पुन नोट किया, "भारत में विकास विशेष रूप से मौद्रिक नीति को मजबूत करने, रुके हुए सुधारों, बिजली की कमी के कारण कमजोर था, जिसने राजकोषीय और मुद्रास्फीति की चिंताओं के साथ-साथ निवेश गतिविधि में कटौती की।"

29. भारत के दूरसंचार क्षेत्र ने 2जी घोटाले और नीतिगत खामियों के कारण एक कीमती दशक गंवा दिया। यूपीए के शासनकाल में, स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और 2008-09 तक के वर्षों में इसका अक्सर दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप "2 जी घोटाला" हुआ और समस्याएं शुरू हुईं जो अंततः इस क्षेत्र में संकट की स्थिति का कारण बनीं। वर्ष 2010 के बाद के वर्षों में प्रचालकों को वस्तुतः बहुत कम या बहुत कम स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा सका,

जिससे दूरसंचार उद्योग का विकास धीमा हो गया। वित्त वर्ष 2009 में जारी किए गए दूरसंचार लाइसेंसों की आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस अवधि में, उच्चतम न्यायालय के फैसले से सरकार के बाहर होने के बाद दूरसंचार क्षेत्र पर अधिकार हो गया। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप, कई ऑपरेटर अव्यवहार्य हो गए, जिससे यह क्षेत्र सीमित प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ गया। इस अवधि में नीतिगत अनिश्चितताओं और कानूनी बाधाओं के कारण विदेशी निवेश का पलायन भी देखा गया।

80:20 गोल्ड आयात-निर्यात योजना का जिज्ञासु मामला

30. **यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई 80:20 स्वर्ण निर्यात-आयात योजना इस बात की मिसाल है कि कैसे सरकारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को तोड़-मरोड़ कर अवैध आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए विशेष हितों की पूर्ति की गई।** निजी फर्मों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विवेकाधीन आधार पर अनुमति दी गई थी। वर्ष 2014 के मध्य में तत्कालीन सरकार ने चुनिंदा प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस (पीटीएच) और स्टार ट्रेडिंग हाउस (एसटीएच) को सोने के आयात की अनुमति दी थी, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू थी और संसदीय चुनावों में डाले गए मतों की गिनती 16 मई 2014 को होनी थी। हमारी सरकार द्वारा वापस लेने से पहले इस कार्रवाई का अर्थ लाभार्थियों को नाजायज़ अप्रत्याशित लाभ देना था।

नीतिगत खामियाँ और परियोजना में विलंब:

31. **यूपीए सरकार का कार्यकाल निर्णय आंकड़ों के उदाहरणों से भरा पड़ा था।** कैबिनेट सचिव ने 2013 में नोट किया था,

> "सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाएं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्रों में, विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण निवेश के लिए रुकी हुई हैं।"

इस अहसास के चलते 2013 में कैबिनेट सचिवालय में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) का गठन हुआ, जो काफी देरी से हुआ। भारत में राष्ट्रीय चुनावों से दो महीने पहले, मार्च 2014 में प्रकाशित हुए वर्किंग पेपर में, दो आईएमएफ अर्थशास्त्रियों ने देश में निवेश के लिए मंदी के तीन कारणों का पता लगायाः नीतिगत अनिश्चितता,

परियोजना अनुमोदन में देरी और विशेषरूप से खनन और विद्युत क्षेत्र[20] में रूकी हुई आपूर्ति और कार्यान्वयन। इन दोनों क्षेत्रों को नीलामियों से त्रस्त कर दिया था और इसलिए न्यायिक जांच के अधीन थे। मार्च, 2015 में क्रिस्टीन लेगार्ड तत्कालीन प्रबंध निदेशक, आईएमएफ कह रहे थे। भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान बनाने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए एपिछली सरकार से इसकी तुलना की "इनमें से बहुत सारी परियोजनाएं अनिश्चितता और नौकरशाही की रूकावट के कारण देरी हुई"।[21]

32. **यूपीए सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का फायदा उठाया, लेकिन उनके द्वारा वादा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने में विफल रही।** आईएमएफ ने वर्ष 2012 में नोट किया कि, "वर्तमान सरकार के गठबंधन जिनसे कार्यान्वयन में गति लाने की आशा थी, के सुधार की गति से कई निवेशक निराश हुए हैं और हाल ही में यह हाई प्रोफाइल स्कैन्डल और अत्यधिक सिविल सक्रियतावाद के कारण अपेक्षाकृत सुस्त सरकारी निर्णयन क्षमता के प्रति चिंतित हो गए हैं।" [22] विशेष रूप से, यूपीए सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का वादा किया था। देश के कोने कोने में 26 दलों का गठबंधन होने के बावजूद सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने में विफल रही क्योंकि यह विभिन्न राज्यों[23] की चिंताओं पर प्रभावी रूप से ध्यान नहीं दे सकी। इस गतिरोध ने संरचनात्मक सुधार पर किसी भी प्रगति को बाधित किया, जिससे हमारी सरकार के सत्ता संभालने तक एक एकीकृत "एक राष्ट्र, एक बाजार" प्रणाली को प्राप्त करने की आकांक्षा को एक अवास्तविक लक्ष्य के रूप में छोड़ दिया गया।

33. डिजिटल सशक्तिकरण के प्रतीक भारत में आधार को भी यूपीए के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। 2006 में यूपीए द्वारा आधार की शुरूआत की गई थी, वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तावित 'बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कार्ड' के विचार का मूर्त विकास था, जिसे भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के आधार पर जारी किया

---

[20] राहुल आनंद और वोलोदिमायर टुलिन (2014) 'इंडियास इंवेस्टमेंट स्लोडाउनः द हाई कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2014/03/25/indias-investment-slowdown-the-high-cost-of-economic-policy-uncertainty)

[21] क्रिस्टीन लेगार्डः 'सिजिंग इंडिया'स मूमेंट', 16 मार्च, 2015 (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2015/03/16/seizing-indias-moment)

[22] भारत के अनुच्छेद IV परामर्श, 2012 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

[23] https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/ub2007-08/bs/speecha.htm

जाना था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) कार्यक्रम शुरू किया, जबकि पूर्व योजना आयोग ने विशिष्ट पहचान परियोजना की देखरेख की। यूपीए सरकार साझा उद्देश्य की कोई भावना स्थापित नहीं कर सकी, और दायरे, उद्देश्य और कार्यान्वयन जिम्मेदारियों में व्यापक अंतर-मंत्रालयी मतभेद थे। यह केवल एनडीए की आधार की पुन: कल्पना थी जिसने आधार को सक्रिय किया, इसे उद्देश्यपूर्ण सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में बनाया जो बिचौलियों की उपयोगिता को खत्म कर देता है, गरीबों को सीधे सब्सिडी की सुविधा प्रदान करता है, डुप्लिकेट लाभार्थियों को छांटता है, और लेनदेन में प्रामाणिकता लाता है। यूपीए सरकार के तहत आधार की कहानी अप्रभावी निर्णय लेने, उद्देश्य की भावना और नीतिगत विफलता की कहानी है।[24]

34. यूपीए सरकार में रक्षा तैयारियों से समझौता करते हुए भ्रष्टाचार और रक्षा में घोटालों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया ठप हो गई। सरकार ने तोपखाने और विमान-रोधी तोपों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, नाइट फाइट गियर और कई उपकरणों के उन्नयन के अधिग्रहण में देरी की।

    एक सुरक्षा विश्लेषक ने 2010 में लिखा था:

    उन्होंने कहा, 'हथियारों की महंगाई दर सालाना 15 प्रतिशत है और पांच साल की देरी का मतलब है कि भारत को जो उसे करना चाहिए था उससे दोगुना भुगतान करना पड़ा। और जब वह उपकरण सरकार-से-सरकार खरीद और अन्य एकल-विक्रेता संविदाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो प्रतिस्पर्धी बोली में लागत लगभग 25 प्रतिशत अधिक होती है। रक्षा मंत्रालय के 50,000 करोड़ रुपये के खरीद बजट में देरी से केवल आधे हिस्से को ही नुकसान पहुंचता है लेकिन भारत ने 25,000 करोड़ रुपये के हथियार, जितना उसे भुगतान करना चाहिए था, से 125 प्रतिशत अधिक कीमत पर खरीदें हैं।"[25]

35. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कई निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं को गलत तरीके से कार्यान्वित किया गया। उदाहरण के लिए, (1) स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के तहत, घरेलू शौचालयों का निर्माण वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 14

[24] यह भी देखें https://indianexpress.com/article/political-pulse/aadhaar-journey-bjp-digital-india-9095394/ ((5जनवरी, 2024

[25] अजय शुक्ला, बिजनेस स्टेण्डर्ड, 23 फरवरी, 2010

के दौरान लक्ष्य का 44 से 52 प्रतिशत रहा। निर्मित शौचालयों में से 33 प्रतिशत निर्माण की खराब गुणवत्ता, अधूरी संरचना, रखरखाव की कमी आदि जैसे कारणों से खराब हो गये थे; (2) रेलवे की 442 चालू परियोजनाओं में से केवल 156 (35 प्रतिशत) परियोजनाओं के पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप 1.07 लाख करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई; (3) कौशल विकास के लिए 57 से 83 प्रतिशत भागीदार वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2014 के दौरान अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे; (4) रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्वास के लिए पहचान करने के बाद पुल कार्यों को स्वीकृत करने में औसतन 43 महीने का समय लिया और उसके बाद भी पुल संबंधी कार्यों को औसतन 41 महीने की देरी से पूरा किया गया।

आर्थिक नाजुकता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेश के माहौल को अहितकर बना दिया

36. **सार्वजनिक टिप्पणीकारों पर आर्थिक मामलों की गंभीर स्थिति नहीं खोई थी**। आर्थिक पर्यवेक्षक के अनुसार,

> *"लोग निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, रुपया, शेयर बाजार सूचकांक, आर्थिक वृद्धि जैसे लगभग हर आर्थिक संकेतक द्वारा दर्ज की गई गिरावट को लेकर चिंतित हैं। केवल मुद्रास्फीति, व्यापार अंतर और राजकोषीय घाटा बढ़ता प्रतीत होता है। इस बात को लेकर भी चिंता करने की वजहें हैं कि सरकार चुनौती के लिए तैयार है या स्थिति को सही ढंग से पढ़ रही है।"* [26]

37. **जहां दुनिया भर के निवेशकों ने व्यापार करने में आसानी की मांग की, वहीं यूपीए सरकार ने नीतिगत अनिश्चितता और परेशानी पैदा की।** शत्रुतापूर्ण नीतिगत वातावरण द्वारा उत्साहहीन आर्थिक वातावरण को प्रबलित किया गया था। यूपीए सरकार की नीति निष्क्रियता और गलत कदमों ने मूल्यवान निजी निवेश को रोक दिया, जो अपने जोखिम पर विकास और नौकरियां पैदा कर सकता था। एक जाने-माने उद्योगपति ने इस स्थिति पर अफसोस जताते हुए कहा, 'हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बात कह रहा हो और हो सकता है कि किसी मंत्री की राय भिन्न हो।

[26] दा आर्बिट्रेरी स्टेट- टीएन निनन- दिनांक 19 मई, 2012, बिजनेस स्टेण्डर्ड

ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता है,"; "स्टील प्लांट के लिए मंजूरी पाने के लिए आपको सात या आठ साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।"[27]

38. **यूपीए सरकार के अंतर्गत निवेश के माहौल को हतोत्साहित करने के कारण घरेलू निवेशक विदेश चले गए।** एक प्रमुख उद्योगपति ने तो यहां तक कहा कि वह इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में निवेश करेंगे क्योंकि लगातार नीतिगत बदलाव उनकी निवेश योजनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी मायूसी और निराशा निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा करने के कारण था।[28]

खोए हुए अवसर

39. यूपीए सरकार का दशक एक खोया हुआ दशक था क्योंकि यह वाजपेयी सरकार द्वारा छोड़ी गई मजबूत आधारभूत अर्थव्यवस्था और सुधारों की गति को भुनाने में विफल रही। कंपाउंडिंग ग्रोथ की क्षमता का कभी उपयोग नहीं किया गया।
40. यह एक खोया हुआ दशक था क्योंकि यूपीए सरकार प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार, दक्षता और विकास के अवसरों का लाभ उठाने में विफल रही। वाजपेयी सरकार ने दूरसंचार सुधारों के लिए आधार रेखा निर्धारित की थी। लेकिन जिस समय दुनिया 3जी के करीब पहुंच रही थी, यूपीए 2जी घोटाले में फंस गया था और बाद में नीलामी को रद्द करना पड़ा था। 2004 में 6 बिलियन डॉलर की पावर हाउस बीएसएनएल यूपीए के दशक में घाटे में चल रही कंपनी बन गई थी। भारत आयातित दूरसंचार उपकरणों पर लगभग 100% निर्भर था।

नेतृत्व का अभाव

41. यूपीए सरकार में बार-बार नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था। यह सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को शर्मनाक ढंग से सार्वजनिक रूप से फाड़े जाने के मामले में पूरी तरह से जनता के सामने आया।

संक्षेप में, यूपीए सरकार के तहत, अर्थव्यवस्था ने अपना रास्ता खो दिया था

---

[27] श्री रतन टाटा ने फाइनेंशियल टाइम्स को साक्षात्कार में, फर्स्टपोस्ट में उल्लिखित thttps://www.firstpost.com/business/tata-bye-bye-even-ratan-tata-has-given-up-on-this-govt-549194.html

[28] मार्च 2013 में श्री कुमार मंगलम बिरला ने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में, "बिलियनेयर हू शुन्ड इंडिया इू यू-टर्न ऑन मोदी ओवरहाल", 12 नवंबर 2014 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-11/billionaire-who-shunned-india-does-u-turn-as-modi-boosts-economy

42. **वर्ष 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में नोट किया गया है कि *"जबकि भारत की हालिया मंदी आंशिक रूप से बाहरी कारणों में निहित है, इसमें घरेलू कारण भी महत्वपूर्ण है।*** *वित्तीय-संकट के बाद प्रोत्साहन के कारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 में मजबूत वृद्धि हुई। तथापि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं से जुड़ी खपत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति सख्त कर दी गई भले ही विकास के लिए बाहरी बाधाएँ बढ़ गई। परिणामी मंदी, विशेषकर वर्ष 2012-13 में, सभी जगह रही है और अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र इससे अप्रभावित नहीं रहा है।"* [29] वर्ष 2013 में आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर बना देने वाले संकट और लगातार नीतिगत विफलताओं से निपटने में अदूरदर्शिता को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करने से भारतीयों द्वारा अनुभूत आत्मविश्वास की कमी और निराशा की गहराई संतुलित ढंग से निरूपित होती है।

43. **यूपीए सरकार के आर्थिक और राजकोषीय अव्यवस्था ने अंततः अपने कार्यकाल के अंत तक भारत की विकास क्षमता को खोखला कर दिया था।** आईएमएफ ने वर्ष 2013 में नोट किया:

> *"विकास मंदी (भारत में) राजकोषीय समेकन और मौद्रिक सख्ती द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। यह हमें क्षमता की कमी के साथ छोड़ देता है ... जैसे-जैसे नई सड़कों, कारखानों, बंदरगाहों और ऊर्जा में निवेश घटा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की गति सीमा भी कम हो गई है.... जैसा कि आप जानते हैं, परियोजनाओं का अनुमोदन बहुत कठिन हो गया है। यह शायद बड़ी परियोजनाओं से संबंधित घोटालों, बढ़ते जटिल और अतिव्यापी नियमों, सभी परियोजनाओं की गहन जांच के कारण है। नौकरशाही की मंजूरी में देरी के कारण सड़क निर्माण, बिजली संयंत्र निर्माण और यहां तक कि नए कारखाने की मंजूरी भी प्रभावित हो रही है। दूसरे शब्दों में, सुधार प्रक्रिया की कठिनाइयों का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है।"*[30]

[29] आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

[30] श्री नाओयूकी शिन्होरा, डीएमडी आईएमएफ (मई 2013) "वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोढ़ और इसका भारत से निहितार्थ

44. **आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास क्षमता को दबा दिया और भारत एक "नाजुक" अर्थव्यवस्था बन गया।** वित्त वर्ष 2012-13 में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत थी जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही और कृषि क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र ने 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। वर्ष 2013 तक, मॉर्गन स्टेनली ने भारत को 'फ्रैजाइल फाइव' की लीग में रखा था - एक समूह जिसमें कमजोर व्यापक आर्थिक मूल सिद्धांतों के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विकास, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बाह्य घाटा और सरकारी वित्त की बिगड़ी हुई स्थिति शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था केवल वर्ष 2004 में 12 वीं सबसे बड़ी से वर्ष 2014 में 10 वीं सबसे बड़ी होने से वर्ष 2005 और वर्ष 2012 के बीच अनुभव की गई उच्च विकास की अल्पकालिक, गुणात्मक रूप से हीन और अस्थिर प्रकृति को उजागर करती है।

45. **अंततः यूपीए सरकार ने 2014 में जो वसीयत की थी, वह संरचनात्मक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था और निराशाजनक माहौल की एक अवांछनीय विरासत थी।**

भाग-2: व्यापक भ्रष्टाचार

46. यहाँ विभिन्न सरकारी गतिविधियों जैसे खरीद, प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन और नियामक अनुमोदन में व्यापक भ्रष्टाचार शामिल था। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खरीद भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थी। घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों ने लोगों के विश्वास को हिला दिया था। कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः-

- **कोयला ब्लॉक आवंटन:** इस वित्तीय घोटाले में सरकार द्वारा निजी कंपनियों को कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार शामिल था, जिससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ, जैसा कि सीएजी[31] द्वारा अनुमान लगाया गया था। यह 2012 में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 204 आवंटनों[32] को रद्द कर दिया। 47 मामलों में न्यायालयों में अंतिम रिपोर्टें दायर कर दी गई हैं और 10 मामलों में अन्वेषण किया जा रहा है। 14 मामलों में आरोपियों को निचली अदालतों ने दोषी ठहराया है। शेष मामलों पर मुकदमा चल रहा है।
- **राष्ट्रमंडल खेल:** यह आयोजन खेलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में व्यापक भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं से प्रभावित हुआ था। 8 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए थे जिन पर दिल्ली की अदालतों में मुकदमा चल रहा है।
- **2जी टेलीकॉम:** इससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। जैसा कि सीएजी द्वारा अनुमान लगाया गया है (3जी स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान की गई दरों पर) [33]। भ्रष्टाचार के मामले अपीलीय अदालत में हैं।
- **शारदा चिटफंड:** यह एक पोंजी स्कीम थी जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन का डायवर्जन किया गया था, और निवेशकों को उच्च लाभ के वादे के साथ लुभाया गया था। यह घोटाला वर्ष 2013 में सामने आया जब समूह बिखर गया, जिससे लाखों निवेशक वित्तीय संकट में पड़ गए।

---

[31] https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2016/Chapter_1_of_eAuction_of_Coal_Mines_Compliance_Audit.pdf

[32] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1989632#:~:text=It%20was%20informed%20that%20before,CMSP%20Act%20in%20March%202015.

[33] https://cag.gov.in/en/audit-report/details/2314 (पीडीएफ का पृष्ठ 8)

- **आईएनएक्स मीडिया मामला:** यह मामला धन शोधन और एक मीडिया कंपनी में निवेश के लिए विदेशी निवेश मंजूरी में अनियमितताओं से जुड़ा था। यह मामला विचाराधीन है।

- **एयरसेल-मैक्सिस:** इस मामले में एक दूरसंचार कंपनी में विदेशी निवेश को मंजूरी देने में अनियमितता और रिश्वत लेने के आरोप हैं। मामले की सुनवाई चल रही है।

- **एंट्रिक्स-देवास डील:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक उपग्रह सौदे में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार, दुर्लभ एस-बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन में अनियमितताएं और देवास मल्टीमीडिया को गलत तरीके से लाभ पहुँचाना इस मामले के प्रमुख तत्व हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के निष्कर्ष की पुष्टि की है। आपराधिक मामले के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

- **नौकरी के लिए भूमि:** इस मामले में रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप 'डी' में प्रतिस्थापनों की नियुक्ति के बदले भूमि या संपत्ति हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त करना शामिल है। इसकी जांच चल रही है।

- **पंचकूला और गुड़गांव में प्राइम लैंड का आवंटन/रिलीज:** ये अनेक मामले हैं जो निजी बिल्डरों की मिलीभगत से प्रमुख भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने और औद्योगिक भूमि को नजदीकी सहयोगियों को आबंटित करने से संबंधित हैं। जांच के बाद, विचारण न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

- **जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन:** यह मामला 'फर्जी' बैंक खाते खोलकर लगभग 44 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़ा है। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

- **एम्ब्रेयर डील:** यह मामला ब्राजील की एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पाप से जुड़ा है। जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और मामला विचारण न्यायालय में लंबित है।

- **पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट:** यह मामला वर्ष 2009 में भारतीय वायुसेना के

लिए 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

- **हॉक विमान खरीद:** यह मामला मैसर्स रॉल्स रॉयस पीएलसी, यूके से हॉक विमान की अधिप्राप्ति में वर्ष 2003 से वर्ष 2012 की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने से संबंधित है। मामले की जांच की जा रही है।

- **आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला:** यह मामला एक रक्षा भूमि परियोजना में अपार्टमेंट के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा था। यह परीक्षणाधीन है।

- **अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला:** हेलीकॉप्टरों की खरीद में रिश्वत दी गई थी।

भाग-3: संकट, निराशा और पक्षाघात की स्थिति से अर्थव्यवस्था का बचाव

47. **जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, अर्थव्यवस्था निराधार थी, आर्थिक नीति में कई 'गलत मोड़ों' से उत्पन्न गहरे संकट के संकेत दिखा रही थी।** भारत के नीति नियोजकों और देश की प्राथमिकताओं के बीच इतना अधिक अलगाव था कि जिसमें देश फंस गया था, चौंका देने वाली आर्थिक और राजकोषीय गड़बड़ी को पलटने और अपनी गतिशीलता और आशावाद को बहाल करने के लिए जनता ने वर्ष 2014 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया।

48. **वर्ष 2014 में जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार और कार्यकल्प करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना, ताकि भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिल सके और साथ ही इसकी वृहद आर्थिक नींव को भी मजबूत किया जा सके।** पूर्ववर्ती दशक में अक्षम नीति डिजाइन और कार्यान्वयन तंत्र पर निर्भरता की विशेषता थी, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थिर अर्थव्यवस्था थी। हमने नीति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करते हुए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यपालिका द्वारा पारदर्शी और स्वच्छ शासन का एक प्रतिमान अपनाया है।

49. **डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने से लेकर खुले में शौच के उन्मूलन तक, और स्वदेशी टीकों का उपयोग करके पूरी पात्र आबादी का सफलतापूर्वक टीकाकरण करने से लेकर निर्यात में पर्याप्त विविधता लाने तक, भारत ने हमारे नए शासन प्रतिमान के तहत उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए हैं।** हमने कानूनों के सरलीकरण और युक्तिकरण के माध्यम से अक्षमताओं की विरासत को दूर किया है, एक विश्वास-आधारित और उत्तरदायी वितरण प्रणाली को अपनाया है, हर क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए व्यापार करने में सहजता से सुधार किया है, मजबूत सहकारी संघवाद के माध्यम से नागरिकों और राज्यों के साथ साझेदारी पर केंद्रित समावेशी और सशक्त योजना डिजाइन की है। विगत मे टुकड़ों में किए जाने वाली वितरण सेवा के विपरीत, हमने सभी योग्य लाभार्थियों के लिए संतृप्ति कवरेज हासिल किया है। हमने कल्याणकारी फोकस को हकदारी-आधारित सहायता से व्यक्तियों को औपचारिक क्षेत्र में एकीकृत करके सशक्त बनाने के लिए स्थानांतरित कर दिया।

50. हमने वांछित विकास परिणामों को प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण के लिए करदाताओं के धन का प्रभावी उपयोग करने के लिए सरकारी खर्चों को तर्कसंगत और प्राथमिकता देने हेतु **एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया।**

51. हमने काले धन का पता लगाने और इसको हतोत्साहित करने के लिए उपाय करना जारी रखा है।

52. **समानांतर में, हमने अर्थव्यवस्था और व्यापार क्षेत्र की स्थिति को मजबूत किया है।** व्यापक सुधार प्रक्रिया की नींव हमारी सरकार के शुरुआती वर्षों में रखी गई थी। आईएमएफ की रिपोर्ट IV रिपोर्ट (2015) में उल्लेख किया गया है कि "भारत के निकट अवधि के विकास के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है और जोखिम से निपटने में हम अब अधिक सक्षम है, जिसमें राजनीतिक निश्चितता में वृद्धि, कई नीतिगत कार्रवाइयों, व्यापार विश्वास में सुधार, वस्तु के आयात की कम कीमतें और जोखिमों को कम करने में मदद मिली है।" "दो साल बाद 2017 के अनुच्छेद की IV रिपोर्ट में, आईएमएफ ने भारत के बारे में अपने आशावाद को और उन्नत किया, जिसमें कहा गया कि "प्रमुख सुधारों के कार्यान्वयन, आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को कम करने और उचित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं में सुधार हुआ है जो व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाते हैं"।

53. **सुधार प्रक्रिया की शुरुआत ने हमारी सरकार के शुरुआती वर्षों में निवेशकों के माहौल में सुधार और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल दृष्टिकोण बनाकर सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया।** उद्योगपति, जो पहले अन्य देशों में निवेश करना पसंद करते थे, उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए एक नई भावना प्रदर्शित की। भारत निवेश करने के लिए अपने देशों की सूची में शीर्ष पर वापस आ गया था।[34] पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक क्षमता में यह भरोसा मजबूत हुआ है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक भारत की विकास क्षमता के बारे में उच्च आशावाद प्रदर्शित करते हैं, अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में प्रचुर अवसरों की उम्मीद करते हैं।

[34] "बिलियनेर हू शन्ड इंडिया डज़ यू-टर्न ऑन मोदी ओवरहाल ", 12 नवंबर 2014 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-11/billionaire-who-shunned-india-does-u-turn-as-modi-boosts-economy)

54. पत्र के इस खंड में विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे हमारी सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा नीतिगत ठहराव, पक्षाघात और कुशासन से अर्थव्यवस्था को बचाया, उबारा और कायाकल्प किया और इसे गतिशीलता और विकास और लोगों में आशा और विश्वास को जगाया।

पिछले दस वर्षों में व्यापक आर्थिक स्थिति: कमज़ोरी से उभरकर मजबूत होना

एक दशक में 'फ्रैजाइल फाइव' से 'टॉप फाइव' तक

55. **वर्ष 2014 में हमारी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक मूल सिद्धांतों को मजबूत किया है।** सरकार की आर्थिक नीति पिछले दशक की क्षति की भरपाई करने और वित्तीय क्षेत्र को पटरी पर लाकर भारत की विकास क्षमता को बहाल करने, व्यापार के लिए स्थितियों को आसान बनाकर आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने और भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और इस प्रकार, इसके विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी नीतियों के मार्गदर्शन के लिए इस दृष्टि के साथ, सरकार ने व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने, जीवन की सुगमता में सुधार और शासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करके अर्थव्यवस्था की क्षमता को बहाल करने और बढ़ाने के लिए विविध आर्थिक सुधार किए हैं। इससे भारत में नीतिगत अनिश्चितता काफी कम हुई, जो यूपीए सरकार के दौरान चरम पर थी।

56. **सुधारों के परिणामस्वरूप लगभग एक दशक में भारत 'फ्रैजाइल फाइव' की लीग से 'टॉप फाइव' की लीग में बदल गया क्योंकि चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बीच अर्थव्यवस्था कहीं अधिक समुत्थानशील अवतार में बदल गई थी (तालिका 3)।** बाहरी उत्पत्ति की अभूतपूर्व बाधाओं (जैसे महामारी, भू-राजनीतिक गड़बड़ी, आदि) के बावजूद पिछले दस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदय इसकी जीडीपी रैंकिंग के प्रक्षेपवक्र में प्रकट होता है। वर्ष 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद, भारत ने वर्ष 2023 में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है (लेकिन वर्ष 2020 में महामारी के लिए, हम कम से कम दो साल पहले 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए होंगे) और आईएमएफ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।

तालिका 1: वर्ष 2012-13 और वर्ष 2021-22 में भारत के व्यापक आर्थिक मूल सिद्धांतों की स्थिति

वृहद आर्थिक आधार	**घटना 1 (2012-13)**	**घटना 2 (2021-22)**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष	-4.8	-1.2
वर्ष दर वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)	5.5	9.1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार	16.0	20.1
वर्ष दर वर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति	9.9	5.5
विनिमय दर मूल्यह्रास (आईएनआर/यूएसडी) (वर्ष दर वर्ष)	6.3	3.1

स्रोतः एमओएसपीआई

भारतीय बैंकिंग प्रणाली: सुस्त हालात से सुदृढ़ीकरण तक

57. **पिछले दस वर्षों में, सरकार ने स्थिर वित्तीय क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है और अर्थव्यवस्था के भीतर ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को दुरूस्त किया है, जिससे महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।** दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कार्यान्वयन और बैंकिंग क्षेत्र के तुलन पत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई और सरकार द्वारा लागू किए गए उपाय (जैसे आस्ति गुणवत्ता समीक्षा, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा, बैंकों का विलय और पुनर्पूंजीकरण) सितंबर 2023 में सकल अग्रिमों के अनुपात में 3.2 प्रतिशत के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के अनुपात में गिरावट आई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बहाल लाभप्रदता तब की तुलना में अब बचाव, वसूली और कायाकल्प की अपनी कहानी कहती है **(तालिका 4)**।

तालिका 4: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख अनुपात (आंकड़े प्रतिशत में)

	वर्ष 2013-14	**वर्ष** 2022-23
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.45	2.72
आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)	0.50	0.79
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	8.48	12.35

स्रोत: आरबीआई

अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए नीतियां

58. **हमारी सरकार के "नेशन फर्स्ट" के दृष्टिकोण ने भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की गुणवत्ता को बदल दिया है, जो देश के लिए निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।** ब्याज भुगतान को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा कुल खर्च में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 24 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया, जो वित्त वर्ष 14 में 16 प्रतिशत था। इसके अलावा, गतिशक्ति का उपयोग करके "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण और प्रगति के माध्यम से निगरानी के कारण पूंजी का उपयोग कैसे किया गया जिसके इसकी दक्षता में सुधार हुआ।

59. उदाहरण के लिए, जब हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2015 में कार्यभार संभाला, तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 12 किमी/दिन थी। वित्त वर्ष 2023[35]में निर्माण की गति 2.3 गुना से अधिक बढ़कर 28 किमी/दिन हो गई। जबकि यूपीए सरकार ने अपने 10 वर्षों के शासन में लगभग 16,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए थे, हमारी सरकार ने अपने लगभग 10 साल के शासन में इससे कम से कम तीन गुना बेहतर काम किया है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 0.98 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1.45 लाख किलोमीटर हो गई है, प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात 581 मिलियन टन से बढ़कर 784 मिलियन टन हो गया है। विद्युतीकृत रेल मार्ग 22,224 कि.मी. (वित्त वर्ष 2015) से बढ़कर 50,394 कि.मी. (वित्त वर्ष 2022) हो गया है। भारत के विमानन उद्योग में पिछले एक दशक

[35] https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1985811

में महत्वपूर्ण वृद्धि और परिवर्तन हुआ है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है (चार्ट 8)।

चार्ट 7: एनडीए के तहत भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार

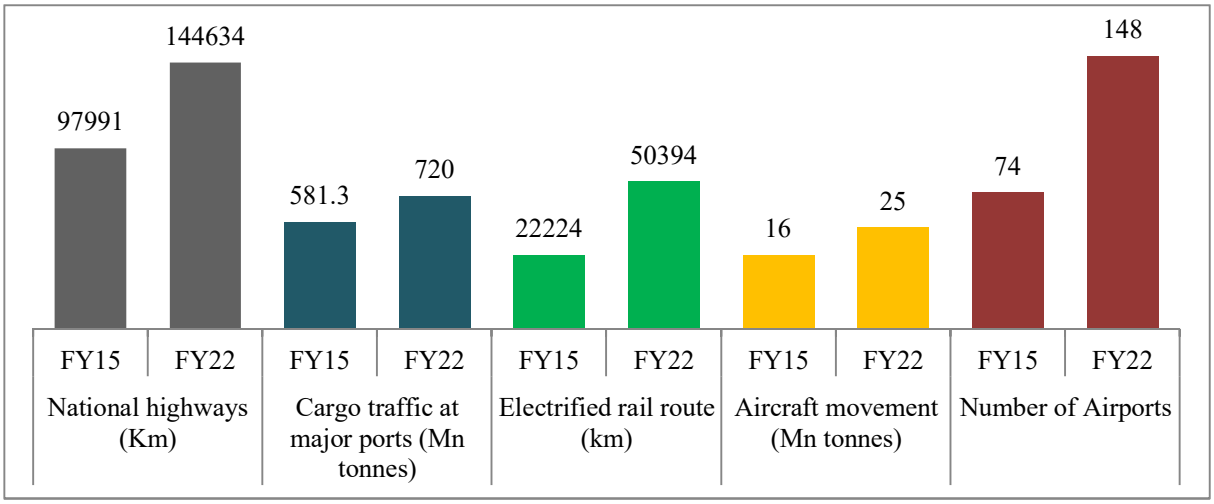

स्रोत: सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय बंदरगाह संघ, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय एवं फरवरी, 2024 का बजट भाषण

60. **इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है को यूपीए सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गई थी। हमारी सरकार द्वारा इस पर जोर दिया गया है।** राष्ट्रीय रक्षा पर उतना ध्यान दिया गया है जितना वह हकदार है। लड़ाकू विमानों की खरीद और पनडुब्बियों का स्वदेशी विकास इसके दो उदाहरण हैं। इसके अलावा, रॉकेट लांचर (आरएल) के लिए थर्मल इमेजिंग (टीआई), नाइट साइट्स फॉर द रॉकेट लॉन्चर (आरएल)[36] और लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एंड ट्रैक सिस्टम (आईआरएसटी) जैसे उपकरणों की तेजी से खरीद के लिए रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इससे रक्षा पूंजीगत अधिप्राप्ति में अत्यधिक विलंब को रोका गया है।

61. हमारी सरकार 'प्रकृति' और 'प्रगति' के बीच संतुलन की सच्ची भावना को समझती है जो 2011 के नियमों में पूरी तरह से लुप्त थी। एनडीए सरकार ने भारत के समुद्र तटों के साथ संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों के संरक्षण और जलवायु-अनुकूलन तटीय जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी है। ये ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें एनडीए सरकार ने सुधारों के माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटीय जिले जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए

[36] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1533669

सुसज्जित हैं, एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है कि ये जिले इन जिलों में समुदायों के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के माध्यम से आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षम हैं। इस प्रकार तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) 2019 पेश किया गया था। यूपीए सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त नियंत्रणों को तर्कसंगत बनाया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि तटीय जिलों को निर्णय लेने का अधिकार है जो उनके समुदायों को लाभान्वित करेंगे। सुधारों से इन तटीय जिलों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अस्थायी और साथ ही अधिक टिकाऊ पर्यटन सुविधाओं जैसे कि होटल और रिसॉर्ट के निर्माण की अनुमति मिलेगी, जो पहले यूपीए सरकार द्वारा "नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)" के रूप में प्रतिबंधित थे। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा पर समान रूप से जोर दिया जाता है।

निवेशकों की भावनाओं को पुनःप्रवर्तन करना

62. हमारी सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों ने अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की निवेश संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक भारत की विकास क्षमता के बारे में उच्च आशावाद व्यक्त करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में आकर्षक अवसरों की उम्मीद करते हैं। जेपी मॉर्गन के सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआई-ईएम) में भारत को शामिल करने की घोषणा अहम घटना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। इससे न केवल भारत को अधिक धन जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार भी बढ़ेगा और भारत को देश की बढ़ती उधार जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, “भारत के इक्विटी बाजारों में निवेश चाहने वाले निवेशकों को पूरा करने के लिए विशेष फंड तैयार किए जा रहे हैं, जैसे की गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो[37]। भारत अब किसी श्रेणी में होना चाहिए और इसे प्रसिद्ध निवेशक और फंड मैनेजर मार्क मोबियस के हालिया बयान से समझा जा सकता है जिन्होंने टिप्पणी की थी कि “भारत अपने आकर्षण

[37] https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/en/fund-literature/monthly-fund-update/mfu_indiaeq_ocssek_en.pdf?sa=n&rd=n

और महान पुरस्कारों के वादों से निवेशकों को चुटकी में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं भी इसकी विशाल विकास क्षमता से मोहित हूँ"[38] ।

सशक्त और प्रभावी संवितरण के माध्यम से लोक कल्याण

63. **कल्याण के माध्यम से सशक्तिकरण हमारी सरकार का ध्येय रहा है। हमने बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को प्रथमिकता देते हुए "सबका साथ, सबका विकास" की विचारधारा को अपनाया और इस विचारधारा को साकार करने में एक भागीदारी**, **मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया।** पिछले दशक में, सामाजिक कल्याण का ध्यान "क्षमता निर्माण के बिना हकदारी" पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक दीर्घकालिक-उन्मुख, कुशल और सशक्त रूप से परिपूर्ण हो गया है। 'किसी को पीछे न छोड़ने' की मानसिकता के साथ, हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की संतृप्ति को आगे बढ़ाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को योग्य लाभार्थियों के लिए लक्षित किया जाए और नकली/अयोग्य प्रविष्टियों को हटा दिया जाए। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल आने वाले दशकों के लिए सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करता है बल्कि व्यक्तियों को जीवन स्तर के मार्ग पर आगे बढ़ने और उच्च विकास के साथ अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

64. **हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित लक्ष्यीकरण और निगरानी तंत्र लागू करके यूपीए सरकार से त्रस्त चुनौतियों का समाधान किया है।** सरकार ने तकनीकी को सामाजिक सशक्तिकरण के साधन और जैम ट्रिनिटी जैसे कि जनधन, आधार और मोबाइल की संभावना को अनलॉक के रूप में उपयोग किया था। इस सरकार ने लीकेज के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी को अंतरित करने की जैम-पहल योजना की प्रथम श्रेणी से लीकेज में 24 प्रतिशत कमी आई है। ''अतिंम छोर तक पहुंच'' के आदर्श से इस सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि आधार की उपयोगिता ने डीबीटी के तहत 1,167 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ रूपये से अधिक की सुविधा प्रदान की है। प्रमुख योजनाओं में उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की सर्वव्यापकता ने वास्तविक- समय निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, एमजीएनआरईजीएस, पीएम-आवास

[38] https://x.com/MarkMobiusReal/status/1742392958467670143?s=20

योजना आदि के तहत आस्तियों की जियो-टैगिंग ने बिग-टिकट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वास्तविक समय (रियल टाइम) में निगरानी और पारदर्शिता को सक्षम किया है। हमारी सरकारी ने परिवर्तित और स्पष्ट पद्धति से इससे पूर्वगामी से अधिक बेहतर कार्यक्रम संवितरण के ट्रैक रिकोर्ड की पराकाष्ठा प्राप्त की है, जैसा की **तालिका 5** में दर्शाया गया है।

तालिका-5 समान उद्देश्यों सहित मुख्य कार्यक्रमों के परिणामों की तुलना

	यूपीए सरकार		एनडीए सरकार	
योजना	**अवधि**	**परिणाम**	**अवधि**	**परिणाम**
किफायती आवास-ग्रामीण	2003-14	2.1 करोड़[39]	2016-2024	2.6 करोड़[40]
शौचालयों का निर्माण	2011-2014	1.8 करोड़ शौचालय निर्मित[41]	2014-2024	11.5 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण[42]
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन	2011-2014	36.4 लाख लाभार्थी[43]	2015-2023	6.1 करोड़ लाभार्थी[44]
न्यूनतम शून्य राशी वाले बैंक खाते	2005-2012	10.3 करोड़ खाते[45]	2014-2024	51.6 करोड़ खाते[46]
ग्रामीण विद्युतीकरण	2005-2014	2.15 करोड़ आवास[47]	2017-2022	2.86 करोड़ आवास विद्युतीकृत[48]

[39] https://164.100.158.235/question/annex/241/Au1406.pdf , https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/New_Reference_Notes/English/RuralHousingIndiraAwasYojana.pdf

[40] https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx

[41] अतारांकित प्रश्न सं. 237, दिनांक 2.12.2015 को उत्तरार्थ, राज्य सभा

[42] https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx

[43] अतारांकित प्रश्न सं. 2657, दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ, लोक सभा

[44] पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

[45] https://pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=84130

[46] https://pmjdy.gov.in/account

[47] लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4448, दिनांक 20.02.2014

[48] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1907728n

किफायती दवाइयां	2008-2014	164 जन औषधि भंडार खोले गए जिनमें से 87 कार्यात्मक[49]	2014-2023	10,000 भंडार खोले गए[50]
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क	2011-2014	6577 किमी ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया[51]	2015-2023	6.8 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया[52]
गरीबों के लिए मातृत्व लाभ	2010-2013	53 जिलों में 9.9 लाख लाभार्थी[53]	2017-2023	पूरे भारत में 3.59 करोड़ लाभार्थी[54]

65. **कार्यान्वयन की भौतिक और डिजिटल दक्षता के अलावा, इस सरकार ने "स्वच्छ भारत", "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" और योजनाओं और कार्यक्रमों के सक्रिय संचार के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक पूंजी का भी उपयोग किया।** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से महिलाओं के समूहों की गतिशीलता का सुउपयोग किया गया है और कार्यक्रम को ग्रामीण परिवारों की 9.9 करोड़ महिलाओं को कवर करते हुए 89.8 लाख एसएचजी[55]में काफी हद तक बढ़ाया गया है। "बैंक सखियों" और "लखपति दीदी" का उद्भव समुदायों में कार्यक्रम नवाचार और स्वामित्व निर्माण का एक परिणाम है।

66. **हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नया रूप दिया है।** उदाहरण के लिए, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के माध्यम से राज्यों में राशन कार्ड की निर्बाध पोर्टेबिलिटी का विस्तार अब देश[56] भर में पूरी एनएफएसए आबादी तक हो गया है, और असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस 'ई-श्रम पोर्टल' का निर्माण प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए पथ-प्रदर्शक सुधार हैं। लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों के साथ पथ-प्रदर्शक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी 'आभा' और ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से और अधिक तकनीकी-सक्षम बनाया जा रहा है।

[49] तारांकित प्रश्न सं. 32, दिनांक 08.07.2014 को उत्तरार्थ, लोक सभा

[50] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988675#:~:text=The%20Prime%20Minister%20virtually%20launched,the%20people%20of%20the%20country.

[51] अतारांकित प्रश्न सं. 1770, दिनांक 03.12.2014 को उत्तरार्थ, लोक सभा

[52] https://usof.gov.in/en/usof-dashboard

[53] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=101140

[54] https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1998748

[55] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1985466

[56] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1990696

स्वामित्व के माध्यम से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड पर जोर ग्रामीण भूमि प्रबंधन और व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण में संरचनात्मक सुधार है।

67. **यूपीए सरकार के कार्यक्रम वितरण में काफी सुधार करने के अलावा, हमारी सरकार ने भारत की विकास क्षमता को उभारने के लिए कई नीतिगत नवाचार भी किए।** स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा योजना के माध्यम से सुलभ ऋण के बड़े पैमाने पर प्रावधान, एसएचजी की अपस्किलिंग और पीएम-स्वनिधि के माध्यम से सड़क विक्रेताओं को ऋण के माध्यम से उद्यमशीलता पर जोर, समाज के सभी वर्गों से नौकरी निर्माताओं को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार के फोकस को दर्शाता है। देश की जनसांख्यिकी और व्यवसाय प्रोफाइल को देखते हुए एक और विचारशील नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच है। हमारी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, दस्तकारों और खिलाड़ियों सहित भारत की विविध आबादी के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अनुकूल बनाया है।

68. पीएम-किसान सम्मान निधि ने किसानों को सशक्त बनाया और उधारकर्ता-ऋणदाता संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी आय में सुधार किया। यूपीए की एडीडब्ल्यूडी ने किसानों को अदा किये जाने ऋण में अटकले पैदा की। इसके विपरीत हमारी किसान सम्मान निधि ने किसानों के ऋण चुकाने की क्षमता को और मजबूत किया है। किसान कल्याण के प्रति हमारे और यूपीए के दृष्टिकोण में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। कल्याण संबंधी वितरण कुशल, प्रभावी और सशक्त है।

परिवारों के लिए उच्च निर्वाह-व्यय की तीव्रता को हटाना

69. **वर्ष 2014 में यूपीए सरकार से प्राप्त उच्च मुद्रास्फीति की स्थायी चुनौती से निपटने के लिए, हमारी सरकार ने जवाबदेह राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा कार्यनीतिक रूप से समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया था।** प्रथम, राजकोषीय सुधार से सरकार के व्यय के निर्णय को सीमित किया गया है। वर्ष 2016 में, सरकार ने लक्षित मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत बैंड के अंदर रखने के लिए आरबीआई को अधिदेश दिया था। वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2023 के बीच औसत वार्षिक मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2004 और वित्त वर्ष 2014 के बीच 8.2 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति से 5.0 प्रतिशत कम हो गई थी **(चार्ट 9)**। यदि भू-राजनैतिक घटनाक्रमों जिनके कारण वैश्विक वस्तु कीमतों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि

हुई थी, जिससे गत 10 वर्षों में औसत मुद्रास्फीति समान रूप से और कम रही होती। फिर भी सरकार ने मुद्रास्फीति को विविध आपूर्ति खातों और मुख्य खाद्य वस्तुओं के बफर के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से नियंत्रित किया है।

चार्ट-9 यूपीए सरकार की तुलना में हमारी सरकार के दौरान औसत हेड्लाइन मुद्रास्फीति

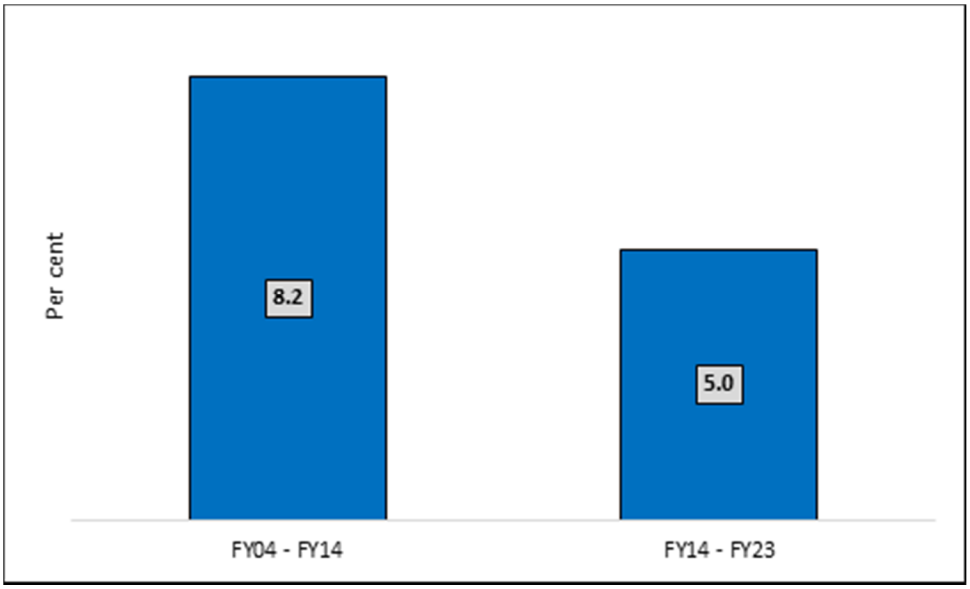

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

विदेशी क्षेत्र भेद्यता को नियंत्रित किया

70. **हमारी सरकार द्वारा यूपीए सरकार से प्राप्त उच्च विदेशी क्षेत्र भेद्यता को नियंत्रण करने के लिए अनुकूल प्रयास किए गये हैं।** सरकार द्वारा दोनों विनिर्माण के साथ-साथ विदेशी व्यापार अन्तर द्वारा शुरू किए गए व्यापक उपायों के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया है। परिणामस्वरूप, जब वैश्विक व्यापारिक निर्यात में लगभग 31 प्रतिशत वृद्धि हुई, तब भारत का व्यापारिक निर्यात कैलेण्डर वर्ष (सीवाई) 2014 से सीवाई 2022 तक उससे अधिक लगभग 41 प्रतिशत बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, जब वैश्विक सेवा निर्यात 36 प्रतिशत तक बढ़ा, उसी समय भारत का सेवा व्यापार 97 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसने जीडीपी के औसत चालू खाता घाटा जो कि वित्त वर्ष 05 और वित्त वर्ष 14 के बीच जीडीपी के औसत 2.3 प्रतिशत था, की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से 1.1 प्रतिशत तक कम करने में योगदान दिया **(चार्ट 10)**।

चार्ट 10 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप स्थिर चालू खाता घाटा

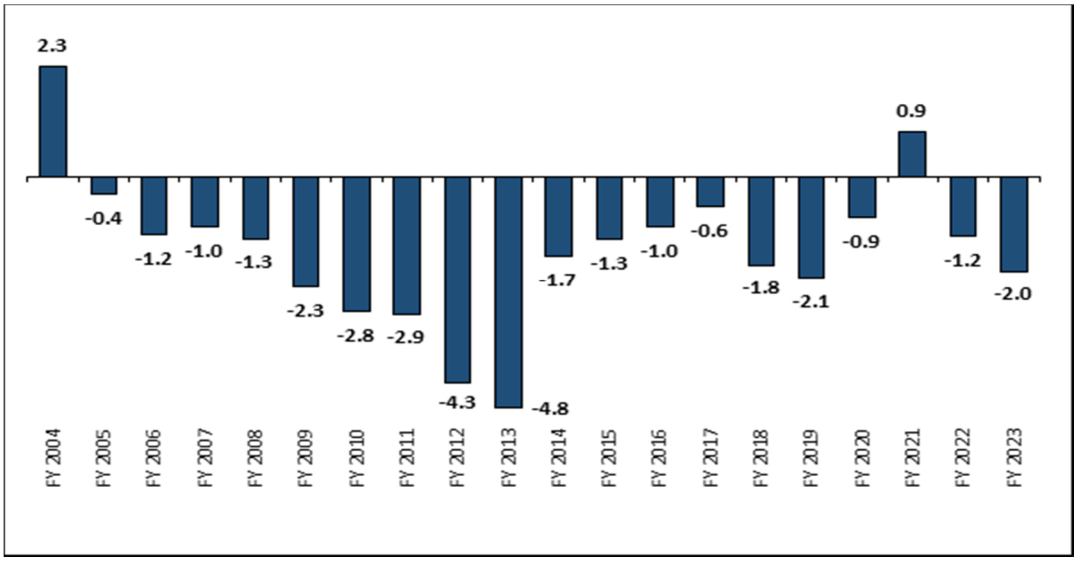

स्रोतः आरबीआई

71. हमारी सरकार द्वारा बहाल अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के कारण, रुपये ने रूस-यूक्रेन संघर्ष और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2021-22 के टेपर टैंट्रम जैसे वैश्विक उतार-चढ़ाव के दौरान लचीलापन प्रदर्शित किया। आरबीआई[57] के वर्ष 2022 के एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि वर्ष 2021 में फेड की टेपरिंग के लिए भारत की प्रतिक्रिया वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत की मजबूत बाहरी स्थिति के कारण विनिमय दर पर कम गंभीर थी. वर्ष 2013 में फेडरल रिजर्व की घोषणा के चार महीने के भीतर ही डॉलर के मुकाबले रुपये में 14.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसके विपरीत, टेपर 2 घोषणा के बाद चार महीनों के भीतर 2021 में रुपये में 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। (चार्ट 11)

[57] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=21140

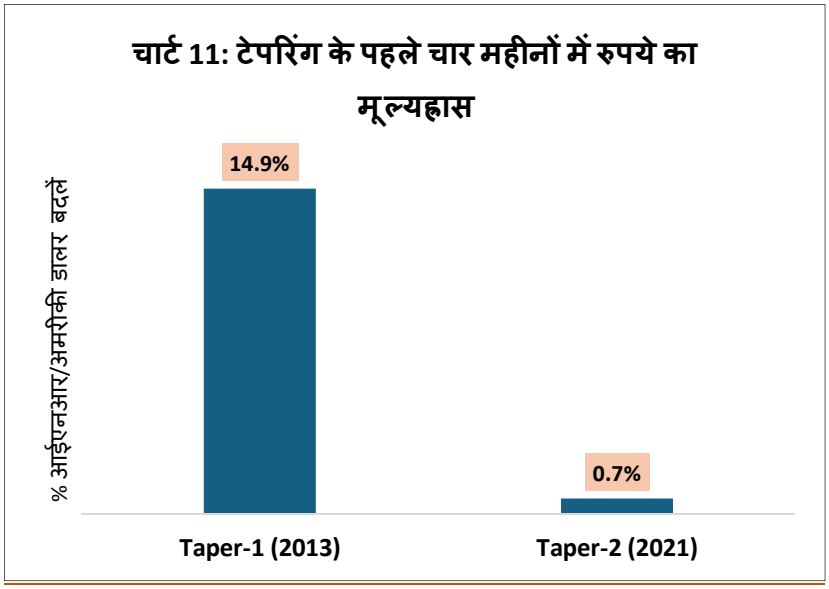

72. **हमारी सरकार ने ना केवल चालू खाता को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया बल्कि आसान और सुविधापूर्ण वित्तपोषण के माध्यम से अधिक स्थिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को सुनिश्चित किया है।** सरकार द्वारा भारतीय उद्योग की प्रतियोगितात्मकता के संवर्धन के लिए तकनीकी और वित्तीय संसाधनों में एफडीआई उदारीकरण उपाय किये गए हैं। इसमें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण को छोड़कर, 100 प्रतिशत एफडीआई खोलना शामिल है। वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2014 के बीच जुटाया गया 305.3 बिलियन अमेरीकी डॉलर के सकल एफडीआई के विपरीत, हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 9 वर्षों में इस राशि का लगभग दुगना (596.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर) संग्रह किया है **(चार्ट 12)**।

चार्ट 10: सकल एफडीआई में रूझान

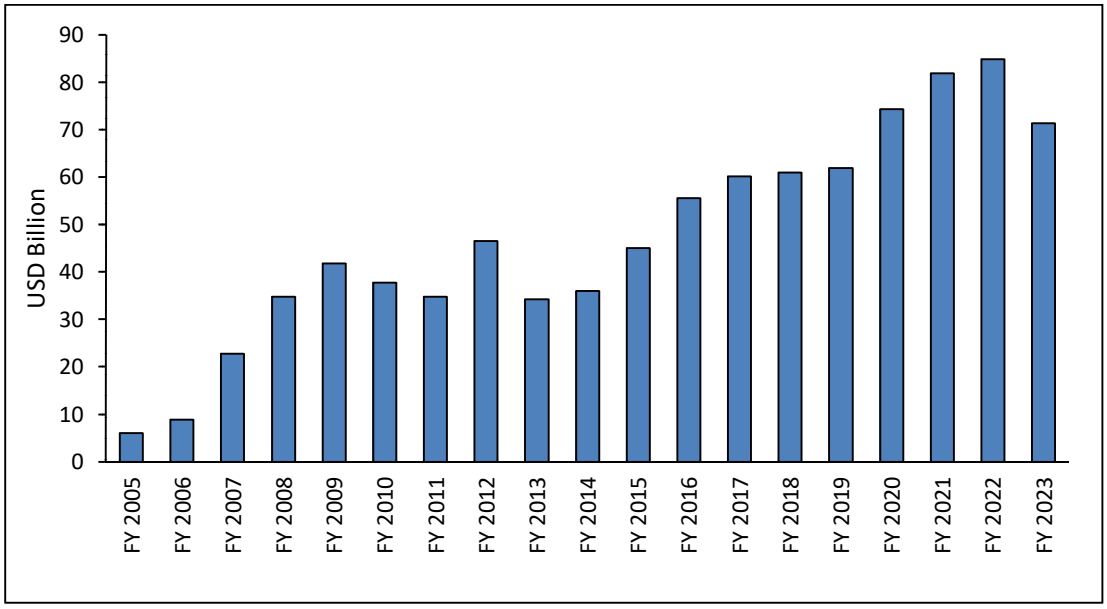

स्रोतः आरबीआई

टिप्पणीः सकल एफडीआई अंतर्वाह सकल अंतर्वाह (पुनर्निवेश अर्जन सहित) है

73. **परिणामस्वरूप, भारत का बाह्य क्षेत्र मार्च, 2014 में 303 बिलियन अमरीकी डॉलर (आयात के 7.8 महीनों के बराबर)[58] से जनवरी 2024 में 617 बिलियन अमरीकी डॉलर (आयात के 10.6 महीने)[59] तक वृद्धि विदेशी मुद्रा प्रारेक्षित निधि (फॉरेक्स रिज़र्व) के साथ, अधिक सुरक्षित है।** भारत ने एक लम्बा सफर तय किया है और वित्त वर्ष 2022 में बढ़ती फेड दरों के खतरे को तब आसानी से कम कर सका जब वैश्विक स्फीतिकारी दबाव में दुनिया में मौद्रिक सख्ती की जा रही थी। पिछले दो वर्षों में भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के सामने विशिष्ट रूप से स्थिर है।

लोक वित्तः दयनीय स्थिति से मजबूत स्थिति तक की यात्रा

74. **जब हमारी सरकार सत्ता में आयी, लोक वित्त अच्छी अवस्था में नहीं था। लोक वित्त को अच्छी अवस्था में लाने के लिए, हमारी सरकार ने भारत की राजकोषीय प्रणाली को बदलने के लिए संवर्धित करों और व्यय परितंत्र में बहुत अधिक बदलाव किए हैं।** काफी समय से लम्बित एक राष्ट्र एक बाजार के लिए जीएसटी जैसे सुधारों की शुरूआत की गई है। हमारी सरकार ने कोविड-19 महामारी के संकटकाल के दौरान

[58] https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=15769

[59] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/RBIBULLETINJANUARY2024EC59F69FFEA5447B9A75C33E7CA8CB26.PDF

अनुकम्पापूर्ण सहायता प्रदान की और पूर्ववर्ती ऑफबजट देनदारियों को उचित बजट खातों में शामिल करके लोक वित्त में पारदर्शिता स्थापित की।

75. **पिछली परिपाटी से हटकर, सीमा से नीचे (बिलो-दी-लाइन) वित्तपोषण का अब पारदर्शी रूप से खुलासा किया जा रहा है।** अब तक, इस सरकार ने 2014 से पहले सब्सिडी के नकद भुगतान के बदले तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की दिशा में पिछले दस वर्षों में लगभग 1.93 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 2025-27 के दौरान यह सरकार शेष बकाया देयताओं और उस पर ब्याज के लिए आगे 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

यूपीए और एनडीए की सरकारों में सरकारी उधारः तुलनात्मक अध्ययन

76. **केंद्र सरकार के बाजार उधार, जो यूपीए के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व दरों पर बढ़े थे, को हमारी सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था।** केंद्र सरकार का निवल बाजार उधार (जी-सेक), जो यूपीए शासन के दौरान 4.4 गुना बढ़ गया था, जबकि सदी में एक बार आने वाली वैश्विक महामारी द्वारा आवश्यक उच्च व्यय आवश्यकताओं के बावजूद हमारी सरकार के तहत 2.6 गुना बढ़ गया।(चार्ट 11)

चार्ट 13: केंद्र सरकार के निवल बाजार उधार (जी-सेक) में वृद्धि

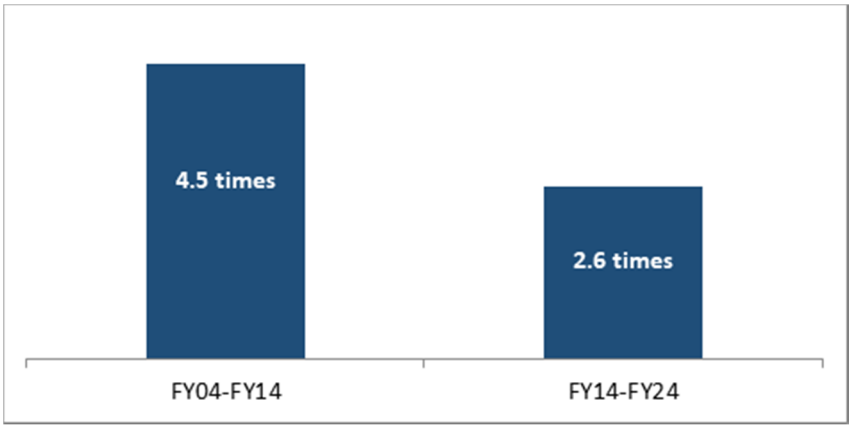

स्रोतः बजट दस्तावेज़ और केन्द्र सरकार के वित्तीय लेखा; वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ें संशोधित अनुमान हैं।

सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में व्यापक परिवर्तन

77. **हमारी सरकार द्वारा व्यय की गुणवत्ता में किये गये सुधार हमारी राजकोषीय नीति की आधारशिला है।** पिछले दशक में हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि निवेश चक्र को गति प्रदान की जा सके और आर्थिक

मंदी तथा लम्बे समय से चली आ रही जड़ता को खत्म किया जा सके। **चार्ट 14** दर्शाता है कि राजस्व व्यय के सीएजीआर में हमारी सरकार के कार्यकाल में यूपीए सरकार की तुलना में कमी आई है। वैकल्पिक रूप से, हमारी सरकार के कार्यकाल में पूंजीगत व्यय में बहुत अधिक औसतन चक्र वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है।

चार्ट 14: पिछले दशक के दौरान व्यय की गुणवत्ता में सुधार

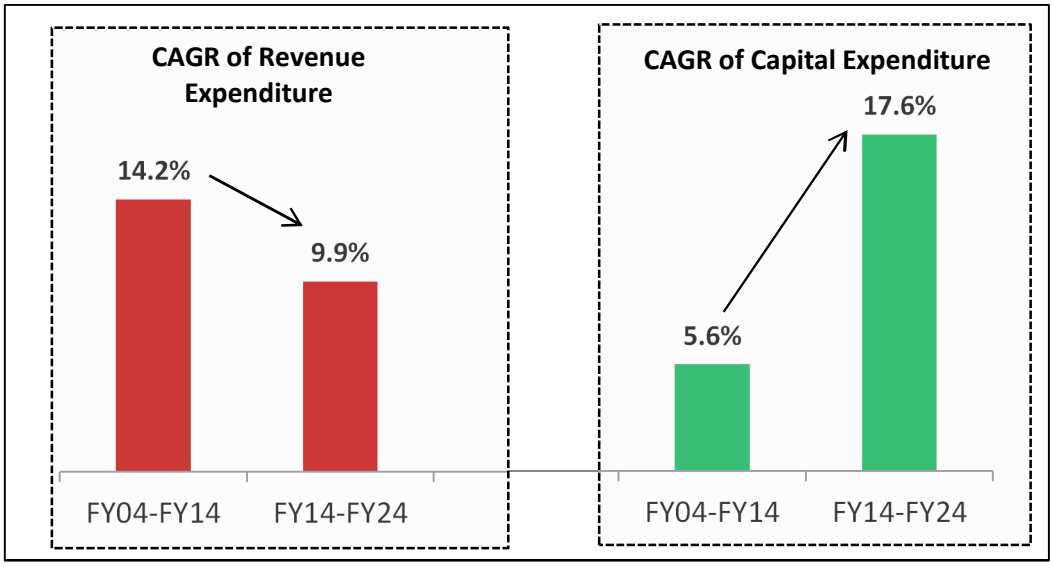

स्रोतः आरबीआई

78. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बजटीय पूंजीगत व्यय में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाए बिना वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 (संशोधित अनुमान) तक पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है (चार्ट 15 बी)। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा, जो वित्त वर्ष 2010 से वित्त वर्ष 2014 के दौरान औसतन 12 प्रतिशत था, वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 (संशोधित अनुमान) के दौरान बढ़कर औसतन 14.5 प्रतिशत हो गया और विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में औसतन 15.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 15ए)। परिणामस्वरूप, 2014 से पहले के चरण के दौरान देखे गए व्यय की गुणवत्ता में गिरावट अब प्रभावी रूप से सुधार हुआ है। लोगों की कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय को फिर से प्राथमिकता दी गई, विशेष रूप से संकट के समय में और प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर लक्ष्यीकरण के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। इससे हमारी सरकार को दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क भोजन कार्यक्रम को लागू करने में मदद मिली, और कोविड-19 संकट के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किए गए।

चार्ट 15: वर्ष 2015 से 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय पर जोर

(क)

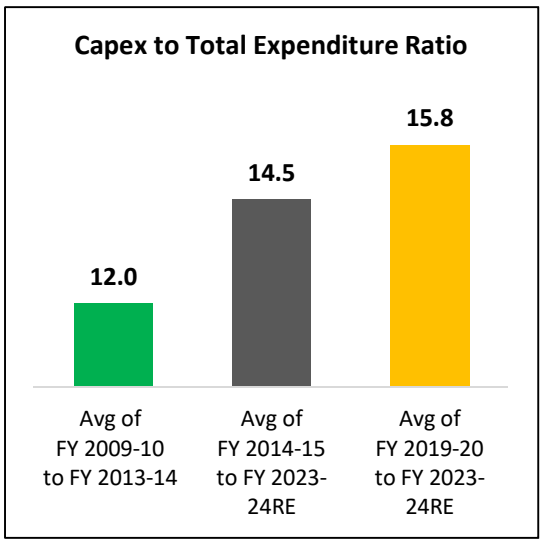

(ख)

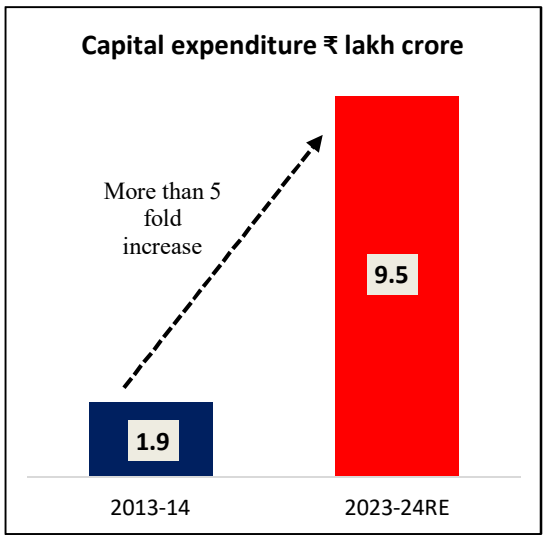

(ग)

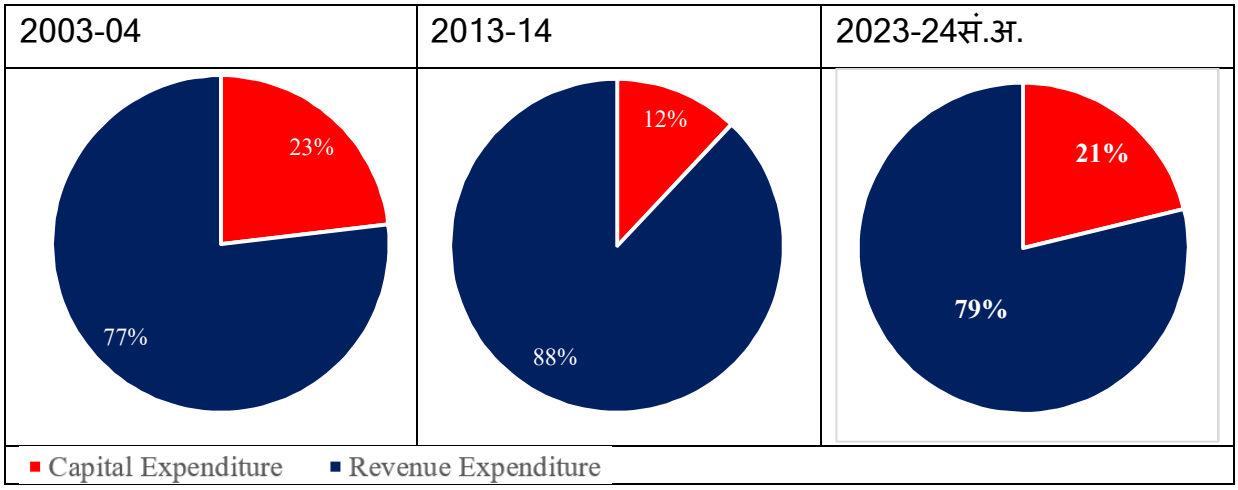

स्रोतः बजट दस्तावेज़

यूपीए सरकार द्वारा चक्रीय राजकोषीय नीति का उपयोग बनाम एनडीए सरकार द्वारा प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति का उपयोग

79. **उच्च विकास अवधि (प्रो-साइक्लिकल) के दौरान बजट बढ़ाने के यूपीए सरकार के दृष्टिकोण के विपरीत, मौजूदा सरकार ने किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पर्याप्त राजकोषीय अवसर उत्पन्न करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के चरम चक्र के दौरान बजट आकार को नियंत्रित करने की एक विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का पालन किया है (काउंटर साइक्लिकल) (चार्ट-16)**। इसलिए, जब कोविड-19 का भारत पर प्रभाव पड़ा, सरकार की प्रतिक्रिया लड़खड़ाते हुए नहीं देखी गई। इसने, बिना किसी देरी के, एक अच्छी तरह से तैयार की गई राजकोषीय

प्रोत्साहन योजना लागू की जो संकटग्रस्त क्षेत्रों और हर व्यक्ति तक पहुँची है। बजट का आकार वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी के 12.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 17.7 प्रतिशत हो गया है। वित्त वर्ष 2021 में पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन के बावजूद, राजकोषीय स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई क्योंकि प्रोत्साहन निरंतर (ओपन-एंडेड) होने की बजाय दूरदर्शी और अंशांकित था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, जैसे ही प्रोत्साहन की आवश्यकता कम हुई, हमारी सरकार राजकोषीय अंतराल के पुनःउद्धार करने के कार्य पर लग गई। जैसा कि आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2022 से प्रभावशाली रूप से प्रतिक्षेप हुआ है, सरकार ने सकल राजकोषीय, राजस्व और प्राथमिक घाटे को लगातार कम किया है। यह दृष्टिकोण राजकोषीय विवेक और पारदर्शिता द्वारा चिह्नित किया गया है। यह वर्ष 2008-09 में जीएफसी के तीन वर्ष बाद वर्ष 2012 में लगातार बढ़ती राजकोषीय और राजस्व घाटे की स्थिति के बिल्कुल विपरीत था।

चार्ट 16: यूपीए कार्यकाल के दौरान प्रो-साइक्लिकल राजकोषीय नीति बनाम एनडीए कार्यकाल के दौरान काउंटर-साइक्लिकल राजकोषीय नीति

यूपीए और एनडीए की सरकार के दौरान कुल व्यय का सीएजीआर

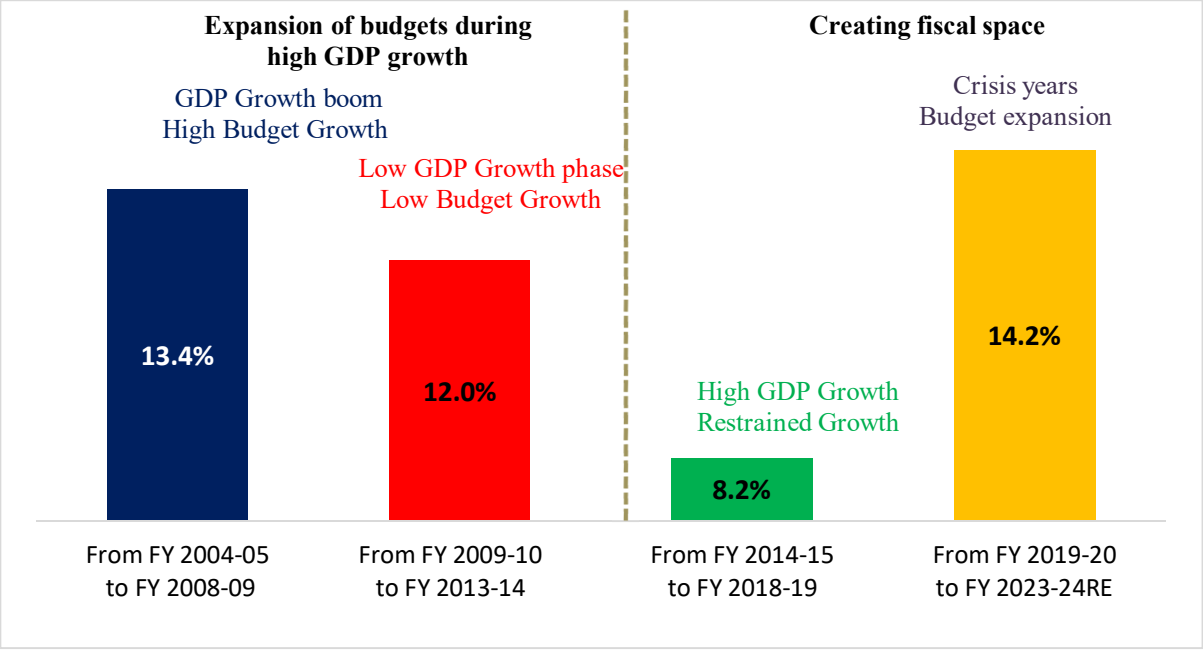

टिप्पणी: संकट के वर्ष कोविड-19 महामारी और कई भू-राजनीतिक संघर्षों को कवर करते हैं जिन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रभावित किया।

स्रोतः बजट दस्तावेज़

पिछले दशक में सुधारीकृत कर पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सुदृढ़ राजस्व वृद्धि

80. **जीएसटी व्यवस्था की शुरूआत अति-आवश्यक संरचनात्मक सुधार था।** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, राज्य लेवी, 440 से अधिक कर दरों, उत्पाद शुल्क और इन दरों को प्रशासित करने वाली कई एजेंसियों की अनुपालन आवश्यकताओं का अर्थ था कि भारत का आंतरिक व्यापार न तो स्वतंत्र था और न ही एकजुट था। सुधार के कार्यान्वयन ने 29 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों को एकजुट किया, जो अपनी विभिन्न कर संरचनाओं के कारण, अपने आप में आर्थिक क्षेत्र थे।

81. **नई कर संरचना की विशेषता राजनीतिक सर्वसम्मति निर्माण** और जीएसटी परिषद की सामूहिक संप्रभुता है, दोनों सहकारी परिसंघवाद के प्रमुख उदाहरण हैं। राज्यों के राजस्व हितों की रक्षा के लिए, जीएसटी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, हमारी सरकार ने जीएसटी राजस्व में 14% की न्यूनतम वृद्धि से किसी भी राजस्व में कमी के लिए **5** वर्षों (2017 - 2022) के लिए राज्यों के लिए मुआवजे की गारंटी दी। जीएसटी सुधार से कई मोर्चों पर लाभ हुआ है। भारत के राज्यों को एक बाजार में एकीकृत करके नई कर संरचना, व्यवसायों में पैमाने को प्रोत्साहित कर रही है।

82. **पिछले दशक के दौरान व्यापक कर सुधारों द्वारा की गई प्रभावी प्रणालियों ने राजस्व संग्रह और अनुपालन को बेहतर किया है।**

- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक संशोधित अनुमान के लिए औसतन कर-जीडीपी अनुपात लगभग 10.9 प्रतिशत है, जो 2004-14 के दौरान दस वर्ष के 10.5 प्रतिशत के औसत से अधिक है। यह कम कर दरों और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान की गई व्यापक राहतों के बावजूद संभव हुआ है।

- गणनाएं यह दर्शाती हैं कि जीएसटी ने दिसंबर, 2017 से मार्च, 2023 तक परिवारों के लिए प्रति माह लगभग 45,000 करोड़ रुपये बचाने में सहायता की। उसी समय में, जीएसटी का मासिक औसत राजस्व वित्त वर्ष 2018 में 90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है **(चार्ट 17)**।

चार्ट 17: औसतन मासिक सकल जीएसटी संग्रह

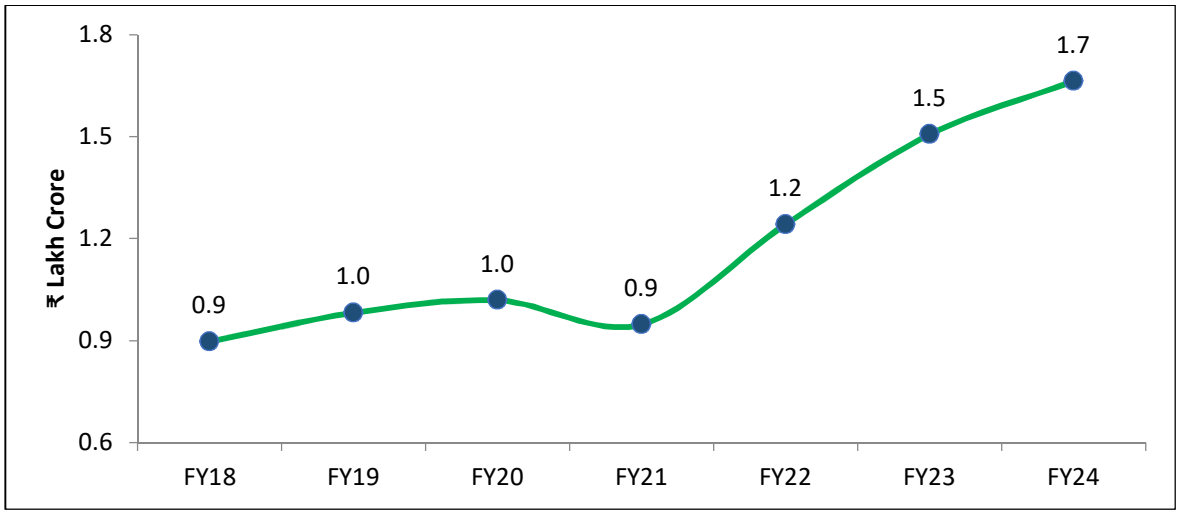

स्रोत: राजस्व विभाग

विकास हेतु राज्यों के साथ संसाधन साझा करना

83. **इस बात को स्वीकार करते हुए कि राज्य विकास में समान रूप से भागीदार हैं, हमारी सरकार ने सहकारी परिसंघवाद का पालन करते हुए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया।** पिछले दशक में, केन्द्रीय करों का लगभग 41-42 प्रतिशत राज्यों के साथ बाँटा गया है। यह पूर्व के 30-32 प्रतिशत के अंतरित हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को अंतरित संसाधनों का हिस्सा पूर्व से लगभग 3.8 गुना अधिक है **(चार्ट 18)**। राज्यों को अंतरित संसाधनों में पूर्ण वृद्धि जीडीपी के लगभग 1 प्रतिशत के समान है।

चार्ट 18: दोनों व्यवस्थाओं के बीच राज्यों को किए गए अंतरण की तुलना

(क) कर अंतरण और एफसी अनुदानों के माध्यम से राज्यों को 3.8 गुना अधिक संसाधन

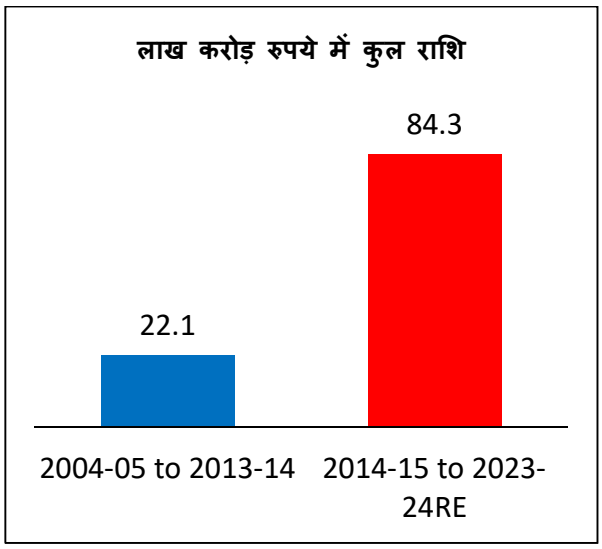

(ख) कर अंतरण और एफसी अनुदानों के माध्यम से राज्यों को जीडीपी के 1 प्रतिशत प्वाइंट के अतिरिक्त संसाधन

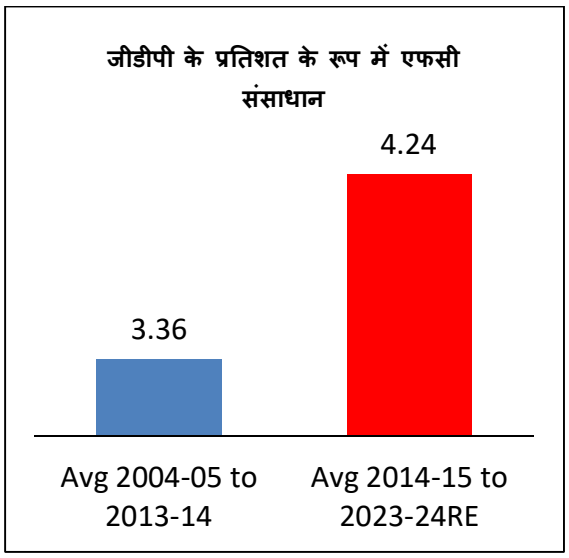

स्रोतः बजट दस्तावेज़

84. **इसके अलावा, परिवर्तित परिस्थितियों के समय में केन्द्र ने राज्यों का भरपूर सहयोग किया है।** राज्यों में यथासमय निधियों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हमने राज्यों को ये भुगतान पहले ही कर दिए थे। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, अतिरिक्त उधार और पूँजीगत व्यय हेतु दीर्घावधिक ब्याज-मुक्त ऋणों ने राज्यों के अनुसार विकास और कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए व्यय हेतु उनके संसाधनों को बढ़ा दिया है।

जन कल्याण हेतु जन संसाधन सुनिश्चित करना

कोयले की लाइसेंसिंग में अंधकार से प्रकाश की ओर

85. **कोयला क्षेत्र में असक्षमता कम करने और प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार द्वारा कई सुधार किए गए।** सत्ता में आने के बाद, हमारी सरकार ने देश के कोयला संसाधनों और ऊर्जा संरक्षा का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करने हेतु त्वरित रूप से कोयला खान विशेष प्रावधान (सीएमएसपी) अधिनियम, 2015 लागू किया। विभिन्न अन्य उपायों में अब तक की पहली कोयला ब्लॉक नीलामी, वाणिज्यिक कोयला खनन, कोयला लिंकेज का युक्तीकरण, कोयले की

ई-नीलामी हेतु एकल विंडो आदि शामिल हैं। कोयला क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023 में कोयला उत्पादन 893.19 एमटी के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया, जो भारत के इतिहास में सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में कोयले के उत्पादन का स्तर वित्त वर्ष 2014 के 565.77 एमटी कोयला उत्पादन की तुलना में करीब 57.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2014 तक कोयले के उत्पादन का सीएजीआर 2.8 प्रतिशत था, यदि यह निरंतर बना रहता तो वित्त वर्ष 2023 में कोयले का उत्पादन 725.39 एमटी होता।

86. हमारी सरकार ने देश के बिजली क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करने वाले कई मुद्दों का समाधान किया है, इस प्रकार इसे बिजली की कमी से बिजली की पर्याप्तता में बदल दिया है। देश ऐसी स्थिति जब दो-तिहाई कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों के पास अत्यलप कोयला भंडार थे(2014), से वर्ष 2015 में उभरकर उस स्थिति में पहुँच गया जब देश में ऐसा एक भी विद्युत संयंत्र नहीं जिसके समक्ष अत्यलप कोयले भंडार का स्तर था। बिजली की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दे को अप्रैल 2014 से 196558 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर संबोधित किया गया है, और भारत ने "एक-राष्ट्र, एक ग्रिड - एक आवृत्ति" का लक्ष्य भी प्राप्त किया है। परिणामस्वरूप, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर 2013-14 में 4.2% से घटकर 2023-24 में 0.3% हो गया है।[60] प्रधानमंत्री के "सहज बिजली हर घर" के दृष्टिकोण के अनुरूप, हर गांव और घर को विद्युतीकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर 20.6 घंटे हो गई है और शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 23.8 घंटे हो गई है। जहां सभी को निरंतर बिजली प्रदान करने के लिए बिजली क्षेत्र में सुधार किया गया है, वहीं पीएम कुसुम योजना अन्नदाता को सक्षम बना रही है- हमारे किसान ऊर्जादाता-ऊर्जा प्रदाता भी बन गए हैं, जिससे 2.46 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।[61]

[60] https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2003172
[61] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944762

दूरसंचार क्षेत्र में बेहतर शासन की शुरूआत

87. **वर्ष 2014 से, हमारी सरकार ने दूरसंचार बाजार में स्थिति को सुधारने और क्षेत्र में नीतिगत स्पष्टता के अभाव के कारण हुई असफलताओं को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए कई कदम उठाए।** इससे स्पेक्ट्रम नीलामी व्यापार और साझेदारी की पद्धतियों में पारदर्शिता आई जिससे स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग सक्षम हो पाया। वर्ष 2022 में 5जी नीलामी के संचालन ने, सबसे उच्चतम नीलामी मूल्य पर, सबसे उच्चतम मात्रा, यानी 52 गिगाहार्ट्स के आवंटन के द्वारा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए संपूर्ण स्पेक्ट्रम उपलब्धता बढ़ा दी। साथ ही, टीएसपी को बेहतर नकदी प्रवाह ने उनको 5जी प्रौद्योगिकी में पूंजीगत निवेश करने के लिए सक्षम बनाया, जिससे देश में 5जी नेटवर्क का शुभारंभ हुआ, जिसे विश्व के सबसे तेज 5जी की शुरूआत के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी उपायों का प्रभाव सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संचयी सकल राजस्व में प्रदर्शित होता है, जो पहले ही 3 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है।

निष्कर्ष

88. यूपीए सरकार अपने दम पर आर्थिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनानें में बुरी तरह से विफल रही। बजाय इसके यूपीए सरकार ने बाधाएं उत्पन्न की जिससे अर्थव्यवस्था अवरूद्ध हो गई। वह वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधारों के अनुगामी प्रभावों की ख्याति और सौम्य वैश्विक स्थितियों का आनंद लेती रही और परिणामस्वरूप संकीर्ण राजनीतिक कार्यों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों पर विचार किए बिना परिणामी तीव्र आर्थिक वृद्धि का दोहन करती रही। इसका परिणाम अशोध्य ऋणों का भार, उच्च राजकोषीय घाटा जिसका अधिकतम हिस्सा अप्रकट था, उच्च चालू खाता घाटा, पांच वर्षों के लिए दो-अंकों की मुद्रास्फीति रही जिससे कई भारतीयों की जमापूंजी पर प्रभाव पड़ा और वर्ष 2013 में "फ्रेजाइल फाइव" के क्लब की सदस्यता मिली। वह न केवल अर्थव्यवस्था में गतिशीलता प्रदान करने में विफल रहे बल्कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को इस प्रकार वंचित किया कि हमारे उद्योगपतियों ने रिकार्ड पर यह कथन दिया कि वह भारत की बजाय विदेशों में निवेश करना बेहतर समझेंगे। निवेशकों को दूर करना आसान है परंतु उन्हें दोबारा वापिस लाना कठिन है। यूपीए सरकार ने इस बात का भी प्रदर्शन किया कि अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाना उसे बढ़ावा देने से ज्यादा आसान है। उन्हें एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली, और उन्होंने क्षीण अर्थव्यवस्था हमें सौंप दी। हमने इसकी जीवंतता का पुनर्रुद्धार किया है। निम्नलिखित बॉक्स उस अंतर को दर्शाता है जो हम पिछले दस वर्षों में कर सकते थे अब हम अगले पच्चीस वर्षों में इसे बढ़ाने की आशा रखते हैं।

• 2014 में जब एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में ही नहीं थी वरन संकटग्रस्त थी। हमने एक दशक के लिए कुप्रबंधित अर्थव्यवस्था को ठीक करने और इसके मूल ढांचों को मजबूत स्थिति में बहाल करने की बहुत सी चुनौतियों का सामना किया।

• तब, हम 'कमजोर पांच' अर्थव्यवस्थाओं में से थे; अब, हम 'शीर्ष पांच' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, जो हर साल वैश्विक विकास में तीसरा सर्वाधिक योगदान देते हैं।

• तब दुनिया का भारत की आर्थिक क्षमता और गतिशीलता से भरोसा उठ गया था; अब, हमारी आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं के साथ, हम दूसरों में आशा का संचार कर रहे हैं। हम अनुलग्नक 1 में दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों की धारणाओं का एक चित्र साझा करते हैं।

• फिर, हमारे पास 12-दिवसीय राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला-भरा था; अब, हमने 2023 में एक बहुत बड़े और साल भर चलने वाले जी20 प्रेसीडेंसी की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें वैश्विक समस्याओं का स्वीकार्य समाधान प्रदान करते हुए सामग्री, सर्वसम्मति और लॉजिस्टिक के मामले में भारत अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित हुआ।

• फिर, 2जी घोटाला सामने आया; अब, हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4जी के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया का सबसे तेज़ 5जी रोलआउट है।

• फिर, कोलगेट घोटाला सामने आया; अब, हमने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीलामी के लिए सिस्टम बनाया है।

• फिर हमने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सोने के आयात का लाइसेंस प्रदान किया; अब, हमने आयात के लिए एक पारदर्शी तंत्र के साथ जीआईएफटी आईएफएससी में एक सर्राफा (बुलियन) एक्सचेंज स्थापित किया है।

• तब, हमारे पास अर्थव्यवस्था 'ट्विन बैलेंस शीट की समस्या' का सामना कर रही थी; अब, हमने अर्थव्यवस्था को कंपनियों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए 'ट्विन बैलेंस शीट लाभ' में बदल दिया है, जिसमें निवेश और ऋण बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है।

• तब मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई थी; अब, मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक तक नीचे लाया गया है।

• फिर, हमारे सामने विदेशी मुद्रा संकट था; अब हमारे पास 620 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है।

• फिर, हमारे पास 'नीतिगत-खामियां' (पॉलिसी पैरालिसिस) थी; बुनियादी ढांचा प्राथमिकता नहीं थी; अब, अधिक निवेश और उत्पादकता के लिए अग्रणी 'निवेश, विकास, रोजगार और उद्यमिता, और बचत' के सुधार चक्र के पहियों में तेजी लाई गई है।

• फिर, हमारे पास विकास कार्यक्रमों का छिटपुट कवरेज था; अब, हमारे पास जरूरतमंदों के लिए सुनियोजित, लक्षित और समावेशी सहायता और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी के सशक्तिकरण के साथ सभी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए 'संतृप्ति कवरेज' (सैच्युरेशन कवरेज) है।

• कुल मिलाकर, हमारी सरकार के दस वर्षों में हासिल की गई प्रगति ने यूपीए सरकार के पिछले दस वर्षों की रूग्णता और गतिहीनता को दूर किया है। वर्ष 2024 में, आत्मविश्वास और प्रयोजन द्वारा वर्ष 2014 के संशय और सुस्ती को प्रतिस्थापित किया गया है। चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक सूची अनुबंध 2 में प्रस्तुत की गई है।

89. हमारी सरकार ने राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता से सशस्त्र होकर, अधिक आर्थिक बेहतरी के लिए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता को पहचाना। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता को पुनः बहाल करना, हमारे मन में सकारात्मकता लाना और हमारी उपलब्धियों में गौरव लाना एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हमें प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमने इस तथ्य को मानते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया कि लोक जीवन लोगों का दिल जीतने एवं उनके मन और मस्तिष्क में जगह बनाने, तथा उनमें उनके तथा उनके बच्चों के भविष्य के प्रति विश्वास भरने के बारे में है। त्वरित उपायों के जाल में वशीभूत होने के बजाय, हमने कठोर सुधार किए ताकि आर्थिक निष्पादन आने वाले दशकों तक संपोषित रहे। हमारी सरकार ने, अपनी पूर्ववर्ती अदूरदर्शी सरकार से भिन्न, सुदृढ़ महासंरचना के निर्माण के साथ अर्थव्यवस्था की नींव में निवेश किया। पिछले दस वर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम विनम्रता और संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया है। इसके बावजूद, हम अपनी सफलताओं पर रूकेंगे नहीं। हमें रुकने से पहले अभी और आगे जाना है और कई चुनौतियों का सामना करना है।

90. अमृतकाल अभी केवल प्रारंभ हुआ है और हमारा लक्ष्य “2047 तक भारत को उन्नत राष्ट्र” बनाना है। यह हमारा कर्तव्य काल है।

अनुलग्नक 1

भारत के प्रति आईएमएफ और विश्व बैंक की अवधारणा का प्रकटीकरण

क्रम संख्या	2014 से पूर्व	2014 के पश्चात
संरचनात्मक सुधार		
1.	**2012 भारत का अनुच्छेद IV परामर्श** कई निवेशकों को वर्तमान सरकार के गठबंधन, जिससे कार्यान्वयन में गति लाने की आशा की गई थी, के सुधार की गति से निराशा हुई है **और वे हाल ही में, हाई-प्रोफाइल शासन घोटालों और नागरिक सक्रियता में वृद्धि के बाद धीमी सरकारी निर्णय लेने के बारे में चिंतित हो गए हैं।**	**सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, एमडी आईएमएफ (अक्टूबर 2022) आईएमएफ/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2022 के दौरान:** भारत इस **अन्यथा अंधेरे क्षितिज पर एक उज्ज्वल स्थान** कहलाने का हकदार है क्योंकि यह इन कठिन स्थितियों के दौरान भी गतिशील वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, **यह विकास संरचनात्मक सुधारों द्वारा रेखांकित किया गया है, उनमें** से डिजिटल आईडी से **भारत में डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय सफलता** से डिजिटल पहुंच के आधार पर सभी सेवाएं और सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।
चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति		
2.	**"भारत: चयनित मुद्दे, 2014" पर आईएमएफ का लेख**: ... क्षेत्रीय बचत-निवेश शेष के संदर्भ में **भारत के चालू खाता घाटे में अभूतपूर्व वृद्धि**। निरंतर उच्च मुद्रास्फीति से **वास्तविक रिटर्न में कमी आई है, जिससे सोने के आयात में वृद्धि हुई है और घरेलू वित्तीय बचत में उल्लेखनीय गिरावट आई है।**	**"2021 भारत का अनुच्छेद IV परामर्श":** **निवल अंतर्वाह और चालू खाते में सुधार ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सहायता की।**

3.	**ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पैक्ट, जून 2012: मैनेजिंग ग्रोथ इन ए वोलाटाइल वर्ल्ड:** घरेलू दबाव देशों में विशेष रूप से तीव्र प्रतीत होता है ... भारत **जहां मुद्रास्फीति अधिक है और राजकोषीय और चालू खाता घाटा बढ़ा हुआ है।**	**ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पैक्ट, जून 2015: हैविंग फिसकल स्पेस एंड यूजिंग इट:** **चालू खाता घाटा और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति- दोनों लगातार अरक्षितताओं- में काफी कमी आई है।** मध्यम अवधि में, विकास दर के लगातार 7 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है क्योंकि सुधारों से उत्पादकता लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है।
व्यापार संबंधी विश्वास		
4.	**"भारत: चयनित मुद्दे, 2014" पर आईएमएफ का दस्तावेज**: वित्तीय सुदृढ़ता के चार सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचकों के आधार पर, **भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र की अरक्षिताएं वैश्विक वित्तीय संकट के निचले स्तर की तुलना से अधिक पाई जाती हैं, और 2000 के दशक की शुरुआत से अपने उच्चतम स्तर पर हैं।** छठा अध्याय भारत में हाल ही में निवेशीय मंदी के कारणों के कारकों की जांच करता है। परिणाम यह दर्शाते हैं कि मानक वृहद-आर्थिक (मैक्रो-फाइनेंशियल) परिवर्तनशील कारकों के अलावा, बढ़ी हुई अनिश्चितता और बिगड़ते व्यापार संबंधी विश्वास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।	**2022 भारत का अनुच्छेद IV परामर्श:** **कार्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र तुलन पत्रों में सुधार आया है।** वित्तीय क्षेत्र की नीतियों ने महामारी के दौरान कॉर्पोरेट क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। उदार मौद्रिक नीति और उधारदाताओं एवं उधारकर्ताओं को लक्षित करने वाली विनियामक सहजता ने वित्तीय क्षेत्र की सहायता करने और क्रेडिट संकट से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तुलन पत्र में भी सुधार हुआ है। ये घटनाक्रम काफी हद तक कॉर्पोरेट क्षेत्र के सुधार को दर्शाते हैं **...**
भारत के निवेश में मंदी		
	राहुल आनंद, वोलोदीमीर टयूलिन (25 मार्च, 2014) द्वारा द हाई कोस्ट ऑफ इकोनोमिक पोलिसी अनसर्टेनिटी :	**आईएमएफ अनुच्छेद IV 2018, भारत:** **मुद्रास्फीति-लक्षित मौद्रिक नीति रूपरेखा**,

5.	**अवसंरचना और कॉरपोरेट निवेश में गिरावट भारत की मौजूदा विकास मंदी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रही है। पिछले दशक के दौरान भारत की निवेश की वृद्धि औसतन 12 प्रतिशत से अधिक थी, जो पिछले दो वर्षों में घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई।** ... **अधिक से अधिक निवेश परियोजनाओं में विलंब हो रहा है और स्थगित कर दिया जा रहा है, जबकि नई परियोजनाओं की पाइपलाइन की स्थिति में असाधारण रूप से कमी आई है।** निम्नलिखित प्रमुख कारक मौजूदा निवेश मंदी के संभावित योगदानकर्ताओं के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं: i बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता। ii. परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन में विलंब। iii.आपूर्ति की अड़चनें:	**माल और सेवा कर (जीएसटी), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की शुरूआत और विदेशी निवेश प्रवाह के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को बेहतर किया है।** सुधारों ने अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए सुलभ बनाने में मदद की है। निदेशकों ने इस बात का स्वागत किया कि पूंजी प्रवाह प्रबंधन ढांचा अधिक उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश** के क्षेत्र में.... निदेशकों ने **बड़े अवसंरचना संबधी निवेश** के माध्यम से अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया।
पूंजीगत प्रवाह में कमी		
6.	**2012 भारत का अनुच्छेद IV परामर्श:** **2011** में आंशिक रूप से भारत के चालू खाता घाटे के कारण, **प्रमुख एशियाई मुद्राओं में रुपये में सबसे अधिक मूल्यह्रास हुआ।** वैश्विक विकास से संबंधित चिंताओं ने **निवेशकों की मंशाओं को ठेस पहुंचाई है** और उन्नत	**2022 भारत का अनुच्छेद IV परामर्श:** **वित्त वर्ष 2021/22 में विदेशी स्थिति मुख्य तौर पर मध्यम अवधि के बुनियादी सिद्धांतों और वांछनीय नीति द्वारा अंतर्निहित थी।** चालू खाता अधिशेष और बड़े पूंजीगत अंतर्वाह ने आरबीआई को महामारी के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय

	अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के ऋणों में कमी (डिलीवरेजिंग) ने विदेशी वित्त की लागत बढ़ा दी है।	भंडार को पुनः पूर्ति करने में मदद की। ... पूंजीगत अंतर्वाह ने निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार करने में मदद की।
विदेशी क्षेत्र		
7.	**इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, अप्रैल, 2013:** **अपेक्षाकृत कमजोर भुगतान शेष (बीओपी) स्थिति के साथ, रुपये ने वित्त वर्ष 2013 के दौरान मूल्य में गिरावट जारी रही और जून में एक सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया,** जो अगस्त तक उसी स्तर पर बना रहा	**ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पैक्ट, जून 2012: डाईवर्जेसिस एंड रिस्कस:** ... **अक्टूबर 2014 से फरवरी 2016 में 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत से भारत में एफडीआई 37 प्रतिशत बढ़ गया है,** जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव क्षेत्रों ने इस निवेश का बड़ा हिस्सा आकृष्ट किया है।

अनुलग्नक-2

क्र. सं.	परिवर्ती	इकाई	स्रोत	तब	अब	टिप्पणी
	वृहद अर्थव्यवस्था					
1	मुद्रास्फिति	प्रतिशत	आईएमएफ	8.2	5.0	तबः वित्त वर्ष 2004 - वित्त वर्ष 2014 के बीच मुद्रास्फीति का सीएजीआर अबः वित्त वर्ष 2014 - वित्त वर्ष 2023 के बीच मुद्रास्फीति का सीएजीआर
2	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी)	पीपीपी डॉलर, मुद्रास्फीति समायोजित	विश्व बैंक	3,889	6,016	तब- वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 के बीच औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी अब- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 के बीच औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी
3	पूंजीगत व्यय	जीडीपी का प्रतिशत	वित्त मंत्रालय	1.7	3.2	तब- वित्त वर्ष 2014 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैपेक्स, अब- वित्त वर्ष 2024 (सं.अ.) के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैपेक्स
4	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात	अमेरिकी डॉलर, बिलियन	वाणिज्य मंत्रालय	7.6	22.7	तब- वित्त वर्ष 2014 के लिए निर्यात, अब- वित्त वर्ष 2024 के लिए निर्यात
5	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	अमेरिकी डॉलर, बिलियन	आरबीआई	305	596.5	तबः वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 के बीच सकल एफडीआई का योग अबः वित्त वर्ष 2015 और नवंबर, 2023 के बीच सकल एफडीआई का योग

6	बहुआयामी गरीबी	जनसंख्या का प्रतिशत	यूएनडीपी, नीति आयोग	29.2	11.3	तब- 2013-14 के अंत में अब- 2023 के अंत तक (अनुमानित)
7	अप्रत्यक्ष कर दर	प्रतिशत	राजस्व विभाग	15	12.2	तब- औसत जीएसटी से पूर्व अप्रत्यक्ष कर दर, अब- मार्च 2023 की तक औसत जीएसटी दर
8	स्टार्टअप- की संख्या	कंपनियों की संख्या	डीपीआईआईटी	350	1,17,257	तब- 2014 तक अब- 31 दिसंबर 2023 तक
9	हावर्ड इकॉनामिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स	रैंकिंग	हार्वर्ड यूनिवर्सिटी	52	42	अब- 2011 में रैंकिंग, अब- 2021 में रैंकिंग (पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक परिष्कृत हुई है। कम संख्या उच्च रैंकिंग का प्रतिनिधित्व करती है।)
क्र.सं .	परिवर्ती	इकाई	स्रोत	तब	अब	टिप्पणी
	भौतिक और डिजिटल अवसंरचना					
10	मेट्रो रेल वाले शहर	शहरों की संख्या	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	5	20	तब- 2014 के अंत में, अब- 2023 के अंत में

11	राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का निर्माण	हजार किमी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	25.7	54.9	तब वित्त वर्ष -2005 और वित्त वर्ष 2014 के बीच निर्मित राजमार्ग; अब- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 (नवंबर) के बीच निर्मित राजमार्ग
12	राजमार्ग निर्माण की गति	किमी/ दिन	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	12	28.3	तब - 2013-14 में गति; अब -2022-23 में गति
13	परिणामी रेल दुर्घटनाएं	दुर्घटनाओं की औसत संख्या	रेल मंत्रालय	233	34	तब वित्त वर्ष -2005 और वित्त वर्ष 2014 के बीच दुर्घटनाओं की औसत संख्या अब - वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2023 के बीच दुर्घटनाओं की औसत संख्या
14	विद्युतीकृत रेल नेटवर्क	हजार किमी	रेल मंत्रालय	21.8	60.8	तब -2014 तक विद्युतीकृत बड़ी लाइन नेटवर्क अब- नवंबर2023 , तक विद्युतीकृत बड़ी लाइन नेटवर्क
15	हवाई अड्डों की संख्या	संख्या	नागरिक विमानन मंत्रालय	74	149	तब - 2014 के अंत में; अब - फरवरी2024 , के अंत तक
16	औसत टोल प्लाजा प्रतीक्षा समय	समय	पी.आई.बी.	12.2 मिनट	47 सेकंड	तब - 2014 में; अब - 2023 में
17	कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता	गीगा वाट	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	249	429	तब - मार्च 2014 तक; अब - दिसंबर 2023 तक

18	स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता	गीगा वाट	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	76	181	तब - मार्च, 2014 तक; अब - दिसंबर, 2023 तक

क्र. सं.	परिवर्ती	इकाई	स्रोत	तब	अब	टिप्पणी
19	लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक	रैंकिंग	विश्व बैंक	54	38	तब- वर्ष 2012 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग, अब- वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग। कम संख्या उच्च रैंकिंग को दर्शाती है।
20	मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	लोगों की संख्या, करोड़	टीआरएआई	6	90	तब- 2013-14 के अंत तक, अब- नवंबर 2023 के अंत तक
21	मासिक डेटा उपयोग	जीबी	टीआरएआई	0.06	18.39	तबः मार्च 2014 के अंत तक अबः जून, 2023 के अंत तक
22	वायरलेस डेटा टैरिफ	रुपये प्रति जीबी	संचार मंत्रालय	269	10.1	तबः 2014 में प्रति जीबी डेटा की रुपए में लागत, अबः 2023 में प्रति जीबी डेटा की रुपए में लागत
	सुरक्षित भविष्य और जीवन यापन में सुगमता					
23	मेडिकल कॉलेज	कॉलेजों की संख्या	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	387	706	तब - 2014 तक; अब- 2 फरवरी, 2024 तक

24	चिकित्सा शिक्षा में सीटें	सीटों की संख्या	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	51,348	1,08,940	तब - 2014 तक; अब- 2 फरवरी, 2024 तक
25	विश्वविद्यालयों की संख्या	मात्रा	शिक्षा मंत्रालय	676	1168	तब- 2013-14 तक, अब- 2021-22
26	वैश्विक नवाचार सूचकांक	रैंकिंग	डब्ल्यूआईपीओ	81	40	तबः 2015 में भारत की रैंकिंग अबः 2023 में भारत की रैंकिंग (कम संख्या उच्च रैंकिंग दर्शाती है)
27	पंजीकृत ट्रेडमार्क	ट्रेडमार्क की संख्या (लाख)	सीजीपीडीटीएम का कार्यालय	8.8	17.9	तब - वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2014 के बीच पंजीकृत ट्रेडमार्क; अब- वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के बीच पंजीकृत ट्रेडमार्क
क्र.सं .	परिवर्ती	इकाई	स्रोत	यूपीए	एनडीए	टिप्पणी
28	एलपीजी कनेक्शन की संख्या	करोड़	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.5	31.4	तब - अप्रैल 2014 तक; अब- अगस्त 2023 तक
29	पीएनजी कनेक्शन की संख्या	लाख	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	22.3	119	तब - अप्रैल 2014 तक; अब- अक्टूबर 2023 तक

30	विद्युतीकरण की स्थिति	प्रतिशत	विश्व बैंक	85.1	100	तब - 2014 तक; अब- 2023 तक
31	बिजली की औसत उपलब्धता (ग्रामीण)	घंटे	विद्युत मंत्रालय	12	20.6	तब- 2014 में उपलब्ध बिजली के घंटों की औसत संख्या अब- 2023 में उपलब्ध बिजली के घंटों की औसत संख्या
32	नल के पानी के कनेक्शन की संख्या (ग्रामीण)	करोड़	जल शक्ति मंत्रालय	3.2	13.8	तब - अगस्त, 2019 तक अब - दिसंबर, 2023 तक
33	डीबीटी लाभार्थियों की कुल संख्या	करोड़	डीबीटी वेबसाइट	10.8	166	तब- वित्त वर्ष 2014 तक अब- वित्त वर्ष 2023 तक
34	विभिन्न योजनाओं के तहत वंचित परिवारों को अंतरित राशि (कुल नकद और वस्तु)	करोड़ रुपये	डीबीटी वेबसाइट	7,367	7,16,396	तब- वित्त वर्ष 2014 के लिए अंतरण, अब- वित्त वर्ष 2023 के लिए अंतरण
35	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण	कुल उत्पादित अपशिष्ट का प्रतिशत	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	18	76	तब - 2014 तक अब- 6 फरवरी, 2024 तक